

दैनिक जागरण

जो विचार आकार न ले सके वह व्यर्थ है

नासूर बना गतिरोध

अमेरिका और ईरान में कोई समझौता होने की संभावनाओं के बीच जिस तरह दोनों किसी सहमति पर भी पहुंचते नहीं दिख रहे हैं, उससे किसी के लिए भी कहना कठिन है कि बातचीत सही दिशा में चल रही है और पश्चिम एशिया संकट शीघ्र समाप्त होने वाला है। पिछले लगभग एक माह से कभी अमेरिका वार्ता के सही दिशा में जारी रहने की घोषणाएं करता है तो कभी ईरान अपने रुख में नरमी दिखाता है, लेकिन परिणाम शून्य है। बीच-बीच में अमेरिका और ईरान, दोनों एक-दूसरे को धमकी भी देते रहते हैं। साफ है कि दोनों का एक-दूसरे के प्रति गहरा अविश्वास है और कथित तौर पर मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान संदेशों का आदान-प्रदान करने के अतिरिक्त और कुछ करने की स्थिति में नहीं। इसका कोई खास मतलब नहीं कि दोनों देशों में युद्धविराम कायम है, क्योंकि वह होर्मुज समुद्री मार्ग बाधित ही है, जिससे विश्व के पांचवें हिस्से की ऊर्जा आपूर्ति होती है। यह आपूर्ति करीब-करीब ठप होने के कारण ऊर्जा संकट गहरा गया है और उसका बुरा असर अमेरिका समेत सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

अब ट्रंप के उन दावों पर भरोसा करना कठिन हो रहा है कि ईरान समझौते के लिए तैयार है। वैसे समझौता न हो पाने के लिए केवल अमेरिका को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ईरान भी इस ज़िद पर अड़ा है कि वह होर्मुज पर अपना आधिपत्य नहीं छोड़ेगा और अपने संबंधित यूरिनियम को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि वह परमाणु हथियार बनाने के इरादे का परित्याग नहीं करना चाहता। इसे कोई भी नहीं चाहेगा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल करे। उसे न केवल परमाणु हथियार हासिल करने के इरादे को छोड़ना होगा, बल्कि होर्मुज पर नियंत्रण रखने की ज़िद भी छोड़नी होगी। होर्मुज एक स्वतंत्र समुद्री मार्ग है और ईरान को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह उसे अपनी निजी जागीर समझ ले अथवा वहां से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूले। यह अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों की अवहेलना करने वाली ज़िद है। ईरान यह दिखा रहा है कि पश्चिम एशिया संकट जारी रहने से उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, पर सच यह है कि वह आर्थिक तबाही के मुहाने पर है। ऐसे में उसे अपनी ज़िद छोड़नी चाहिए। बदले में अमेरिका को भी उसे यह भरोसा दिलाना होगा कि उस पर फिर हमला नहीं होगा। दोनों देशों को यह समझना होगा कि उनके बीच का गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। बहुत हो चुका। अब यह गतिरोध टूटना चाहिए, क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों की रोजी-रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्क्रम से भी घिरे जा रहे हैं।

लापरवाही की हद

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का पिलर टूटने और उस पर टिके स्लैब के गिरने से हुए हादसे में छह लोगों की मौत केवल दुर्घटना नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता है। यह हादसा सरकारी परियोजनाओं में व्याप्त जवाबदेही की कमी, लापरवाही और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। इस बात की जांच सघनता से होनी चाहिए कि पुल निर्माण की खामियों पर डीएम की आपत्ति के बाद भी आवश्यक प्रबंध क्यों नहीं हुए? आपदा को हादसे का कारक नहीं बनाया जा सकता है। जहां पुल बन रहा है, वहां की मिट्टी के नमूने शुरूआती परीक्षण के दौरान मानकों पर खरे नहीं उतरे थे और जो पिलर टूटा है, उसमें पहले भी दरारें आ गई थीं। सुरक्षा मानकों को भी निर्माता कंपनी और ठेकेदारों ने ताक पर रखा। पहले से खराब मौसम के अलर्ट के बाद भी अपर्याप्त रोशनी में निर्माण कार्य रात में जारी रखा गया। घटना के बाद केवल निलंबन और विभागीय जांच पर्याप्त नहीं। शासन को चाहिए कि जहां भी ऐसा निर्माण हो रहा है, वहां सुरक्षा मानकों और गुणवत्ता का अंकेक्षण कराए। लापरवाह अधिकारियों, इंजीनियरों और निर्माण कंपनी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से प्रदेश की छवि आहत हुई है। कठोर निगरानी एवं नियंत्रण आवश्यक है, अन्यथा विकास परियोजनाएं जनता के लिए सुविधा की जगह खतरा बनती जाएंगी।

कठोर निगरानी आवश्यक है, अन्यथा विकास परियोजनाएं जनता के लिए सुविधा की जगह खतरा बनती जाएंगी

कर्नाटक में बदलाव के बाद की चुनौतियां



संजय गुप्त

कर्नाटक में चुनाव दो वर्ष बाद होने हैं। कहना कठिन है कि तब क्या होगा, पर याद रहे कि राज्य में 1980 के बाद कोई भी सरकार सत्ता में नहीं लौटी है

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के त्यागपत्र देने के साथ ही उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के राज्य की कमान संभालने का रास्ता साफ हो गया। इससे शिवकुमार की तो चाहत पूरी हो गई, लेकिन यह कहना कठिन है कि कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ सामान्य होने जा रहा है या फिर राज्य की विभिन्न समस्याओं के समाधान की राह आसान हो गई है। सिद्धरमैया ने त्यागपत्र देने की घोषणा करते हुए यह कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने जैसा कहा, मैंने वैसा किया, लेकिन उन्होंने राज्यसभा आकर कांग्रेस की केंद्रीय स्तर की राजनीति में सक्रिय होने का आग्रह ठुकराते हुए कहा कि वे राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे।

चूंकि सिद्धरमैया जमीनी स्तर की राजनीति करने वाले नेता हैं और उनका अपना जनाधार है, इसलिए वे मुख्यमंत्री बनने जा रहे शिवकुमार के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं। इसके तर्जों में यहां अंदर से गुटबाजी भी पनप सकती है, क्योंकि शिवकुमार के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल से सिद्धरमैया के कुछ समर्थक बाहर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह स्वाभाविक ही है कि शिवकुमार अपने हासिल से शासन चलाएंगे और इसके लिए वे प्रशासन में भी पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थकों को किनारे

कर सकते हैं। इसके आसार कम ही हैं कि सिद्धरमैया अपने उत्तराधिकारी शिवकुमार के लिए खुला मैदान छोड़ेंगे, क्योंकि जमीनी राजनीति करने वाला कोई नेता अपना राजनीतिक वर्चस्व इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। अपने देश में तो ऐसा और भी कम होता है। अपने यहां उम्मेदवार नेता तब तक राजनीति से रिटायर ही नहीं होते, जब तक उन्हें बिखुल किनारे न कर दिया जाए। कांग्रेस सिद्धरमैया की उपेक्षा करने का जोखिम नहीं उठा सकती।

शिवकुमार 2023 में तभी से मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी थे, जब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने वरिष्ठता के आधार पर सिद्धरमैया का चयन किया। शिवकुमार का दावा था कि उनके और सिद्धरमैया के बीच इसे लेकर सहमति कायम हुई थी कि दोनों ढाई-ढाई वर्ष तक सत्ता संभालेंगे। अपने इस दावे के अनुरूप वे पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री पद पर सिर से गुटबाजी भी पनप सकती है, क्योंकि शिवकुमार के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल से सिद्धरमैया के कुछ समर्थक बाहर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह स्वाभाविक ही है कि शिवकुमार अपने हासिल से शासन चलाएंगे और इसके लिए वे प्रशासन में भी पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थकों को किनारे



अवधेश राजपूत

पायलट के बीच भी इसे लेकर खींचतान हुई थी कि दोनों के बीच ढाई-ढाई साल तक मुख्यमंत्री बनने की सहमति बनी थी। सचिन पायलट ने बहुत कोशिश की कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले, लेकिन अशोक गहलोत टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों को भी ठुकरा दिया। इस कारण सचिन पायलट एवं उनके बीच खींचतान जारी रही और कांग्रेस आलाकमान अंत समय तक कोई फैसला नहीं कर सका। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में हुआ। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव के बीच इसे लेकर झगड़ा होता रहा कि ढाई-ढाई साल तक सत्ता संभालने की बात हुई थी। यहां भी कांग्रेस नेतृत्व कोई फैसला नहीं कर सका। नतीजा यह हुआ कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की पराजय का एक कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए खींचतान भी बनी।

कांग्रेस नेतृत्व ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को विधानसभा चुनाव के करीब एक वर्ष पहले मुख्यमंत्री पद से

हटने के लिए बाध्य किया, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके बजाय चरणजीत सिंह चन्नी को मिली। इसके चलते गुटबाजी को बढ़ावा मिला और इसका लाभ आम अदमी पार्टी ने उठाया। कर्नाटक में दो वर्ष बाद चुनाव होने हैं। कहना कठिन है कि तब क्या होगा, लेकिन यह ध्यान रहे कि कर्नाटक में 1980 के बाद कोई भी सरकार सत्ता में नहीं लौटी है। शिवकुमार इस सिलसिले को तोड़ सकेंगे, यह कहना इसलिए कठिन है, क्योंकि कर्नाटक कई समस्याओं से घिरा है।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु आइटो सिटी के रूप में विख्यात है, लेकिन इस समय बेंगलुरु के साथ देश भर का आइटो उद्योग समस्याओं से घिरा है। कर्नाटक में बेंगलुरु को छोड़कर एक दो शहर ही सही तरह विकसित हो पाए हैं। बेंगलुरु और शेष राज्य में जो आर्थिक असमानता दिखती है, वह यह बताती है कि सरकारों ने अन्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं

जनता को मिले भड़ास थेरेपी का सहारा

हार्य-व्यंग्य



हमारे देश में गाली देना हर नागरिक का अघोषित मौलिक अधिकार सा हो गया है। लोग इस अधिकार का बहुतायत से प्रयोग करते रहते हैं। जबकि संकोची यदा-कदा...वह भी मन ही मन...तिलमिलाकर। इतिहास में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि पहली गाली किसने, किसको और किसलिए दी, किंतु यह निर्विवाद सत्य है कि समाज में गालियों का इस्तेमाल प्राचीन काल से हो रहा है। एक वर्ग का मानना है कि गाली-गलौज सभ्य लोगों को शोभा नहीं देती। जबकि दूसरे वर्ग का सोच है कि 'गाली' तो एक वरदान है, जो जीवनपर्यंत मनुष्य के साथ रहता है। इसलिए वह अशोभनीय कैसे। बहरहाल इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि गाली बकने के बाद असीम आत्मिक संतुष्टि मिलती है। ये बात उससे पुष्टि, जो भीतर से भरा बैठा हो और उसकी कुंठा कहीं से भी बाहर न निकल पा रही हो। फिर 'गाली थेरेपी' का सहारा लेकर वह कैसे परम आनंद की प्राप्ति करता है।

गाली को यदि खाद्य पदार्थ कहा जाए तो यह सर्वाधिक सरकारी विभागों के हिस्से में आता है। देश में आमतौर पर हर नागरिक किसी न किसी सरकारी विभाग से पीड़ित होता है। महीनों चक्कर लगाने के बाद भी जब काम नहीं होता तो संस्कारी



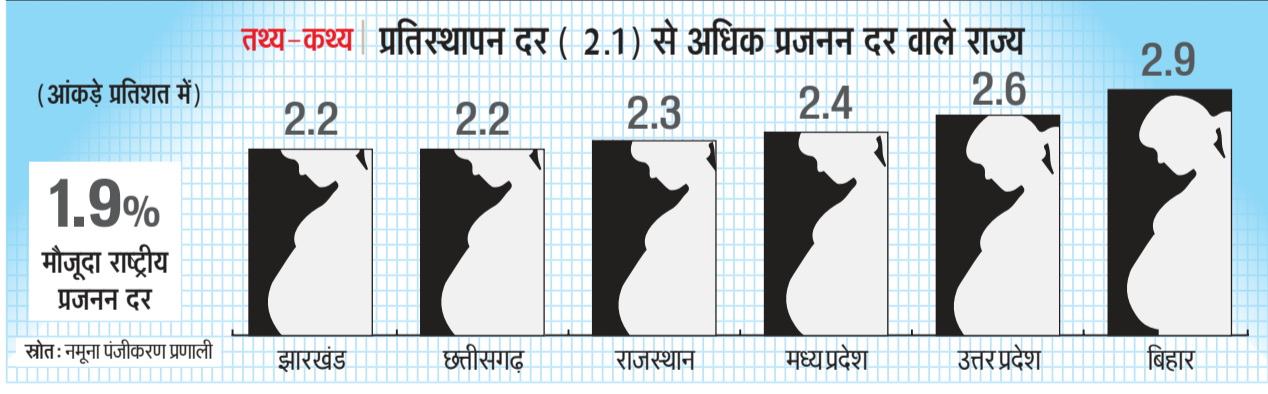
कमल किशोर सक्सेना

आदमी की समस्या मले लटकी रहे, किंतु यदि वह संबंधित लोगों को जीमट गालियां सुना ले तो खुश हो जाता है

नहीं होना चाहिए। प्रस्तावित काउंटर में आवेदक को पहले एक फार्म भरने को दिया जा सकता है। जिसमें नाम-पता लिखने और आधार कार्ड की फोटो कापी संलग्न करने के बाद गाली देने का कारण लिखना होगा। यह भी स्पष्ट करना होगा कि आवेदक साधारण गालियों देना चाहता है या सात गुहरें तारने जैसी।

यदि कोई आवेदक गालियों के साथ जूते मारने की भी इच्छा रखता है तो उसे सशर्त अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद निर्धारित शुल्क जमा करके और गाली देने/जूता मारने का समय एलाट किया जा सकता है। विभिन्न विभागों में ऐसे काउंटर खुल जाने से जनता को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। बस एक आशंका है कि यह योजना भी लालफीताशाही और भ्रष्टाचार का शिकार हो सकती है। तब अखबारों में इन हेडलाइंस से खबरें छप सकती हैं- 'भड़ास काउंटर एक हफ्ते से खाली, कोई कर्मचारी बैठने को तैयार नहीं', 'अनुमति मिलने के बाद भी लाभार्थी गाली देने से वंचित', 'अफसर के चहेते कर्मियों की गाली काउंटर पर ड्यूटी नहीं', 'गाली कोष में लाखों का गबन, काउंटर बंद, जनता में आक्रोश', 'रामू ने फार्म भरा, जूते श्यामू मार गये', 'जूता खाने वाले कर्मियों की हेलमेट की मांग।'

response@jagran.com



इबोला का प्रकोप रोकने की चुनौती

मुकुल व्यास

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ कांगो (डीआरसी) के इटूरी प्रांत में इबोला वायरस के प्रकोप पर काबू पाना कठिन होता जा रहा है। डीआरसी के अलावा युगांडा में भी इबोला के मामले आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला के प्रकोप से होने वाली मौतों की दर 30 से 50 प्रतिशत बताई है। इसका मतलब है कि हर 10 में से 5 लोगों का जान जाने की आशंका है। अफ्रीका के इस हिस्से में लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध की वजह से इबोला के संक्रमण पर काबू पाना और मुश्किल हो गया है। बीमारी के फैलने के केंद्र में मौजूद अस्थिरता के हालात में संक्रमक बीमारियां तेजी से पनपती हैं और अक्सर उनके फैलने का पता भी नहीं चल पाता। वायरस का पहला पक्का मामला गोमा के एक निवासी का था। गोमा एक ऐसा कस्बा है जो खांडा की सीमा पर बसा है और वहां हालात बहुत ज्यादा अस्थिर हैं। बीमारी के फैलने का दूसरा बड़ा कारण यह है कि इसके डिटेक्शन में बहुत देर लगती है। लैब में

इबोला वायरस जानवरों को संक्रमित करते हैं, अगर लोग उनके सीधे संपर्क में आते हैं, तो वे भी संक्रमित हो सकते हैं

किसी संक्रमक रोगाणु की पहचान करने में लगने वाला समय इस बात पर निर्भर करता है कि रोगाणु को बढ़ने में कितना समय लगता है और लैब टेस्ट किस तरह के हैं। यह भी देखा जाता है कि एंटीबायोटिक बंदने में कितना समय लगता है। आम तौर पर इबोला वायरस के लिए यह समय एक से 32 दिन के बीच होता है।

स्थानीय सांस्कृतिक प्रथाएं भी रोग को फैलाने में मदद करती हैं। सिएरा लियोन और डीआरसी जैसे कई अफ्रीकी देशों में रीति-रिवाजों के अनुसार शवों को दफनाना एक आम प्रथा है। ये ऐसी रस्में हैं, जो इस विश्वास से उपजी हैं कि मृत्यु किसी दूसरी दुनिया या पूर्वजों के लोक में जाने का एक पवित्र मार्ग है। इसकी शुरुआत आमतौर पर सामूहिक शोक और रात भर जागकर शव की निगरानी करने

से होती है, जिसके बाद शव को विधि-विधान से अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जाता है।

इबोला वायरस स्वाभाविक रूप से जानवरों, मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों को संक्रमित करते हैं, लेकिन अगर लोग उनके सीधे संपर्क में आते हैं, तो वे भी संक्रमित हो सकते हैं। वर्तमान प्रकोप का कारण इबोला वायरस की बुंडिबुग्यो प्रजाति है। यह उन तीन प्रजातियों में से एक है, जिनके कारण संक्रमण फैलता है। बुंडिबुग्यो ने पहले केवल दो बार प्रकोप फैलाया है। 2007 और 2012 में इसने संक्रमित लोगों में से लगभग 30 प्रतिशत की जान ले ली थी। बुंडिबुग्यो वायरस स्वास्थ्य कर्मियों के समक्ष कई तरह की चुनौतियां खड़ी करता है। इबोला वायरस की अन्य प्रजातियों के विपरीत बुंडिबुग्यो के लिए कोई भी स्वीकृत टीका या दवा उपलब्ध नहीं है, हालांकि कुछ प्रायोगिक दवाएं अवश्य मौजूद हैं। कोई भी स्वीकृत दवा उपलब्ध न होने के कारण इसका इलाज सिर्फ बेहतर देखभाल पर निर्भर करता है।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

अफसरशाही के खेल

'टू डाल-डाल, मैं पात-पात' वाली कहावत तो सभी ने सुनी होगी। हाल ही में नीट-यूजी पेपर लोक मामले के बाद जब संसदीय समिति ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीई) के अधिकारियों को तलब किया तो इसका एक उदाहरण देखने को मिला। हुआ यह कि पेपर

लोक से नाज संहति इस मामले में अधिकारियों से सवाल-जवाब करने की पूरी तैयारी के साथ बैठक में पहुंची थी, लेकिन बैठक शुरू होते ही अधिकारियों ने यह कहकर चर्चा की पूरी दिशा बदल दी कि पेपर लोक हुआ ही नहीं था। समिति के सदस्य यह सुनकर चौंकर रह गए। जब उनसे पूछा गया कि फिर आखिर हुआ क्या था तो जो जवाब मिला, उसे सुनकर सदस्य एक-दूसरे का मुंह ताकने लगे। अधिकारियों ने कहा कि पेपर लोक नहीं हुआ था, बल्कि 'कंप्रोमाइज' हुआ था। यानी कुछ लोगों को प्रश्नपत्र की जानकारी पहले से मिल गई थी, उन्होंने उसे याद कर लिया और फिर परीक्षा में उसी के आधार पर उत्तर लिख दिए, लेकिन शब्दों के इस

राजरंग

जाल से सच्चाई नहीं बदल जाती। तथ्य यही है कि कुछ अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र की जानकारी परीक्षा से पहले ही मिल गई थी। चाहे उसे पेपर लोक कहा जाए या 'कंप्रोमाइज', इससे परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। वैसे भी जिस तरह एनटीई लगातार विवादों और गलतियों के कारण चर्चा में रहा है, उसके बाद अधिकारियों के शब्दों की बाजीगरी से बाहर निकलकर व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

कांटों का ताज!

कर्नाटक में डीके शिवकुमार की सबसे बड़ी खाहिश पूरी होने जा रही है। वे मुख्यमंत्री पद पर आसिन होंगे, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का आकलन है कि यह खुरी वस्तुतः कांटों का ताज साबित हो सकती है। ऐसे समय में मिली है, जब सरकार के पास प्रभावी रूप से केवल डेढ़ वर्ष का ही समय बचा है। आखिरी छह महीने तो चुनावी तैयारियों में ही निकल जाएंगे। यानी डेढ़ वर्ष में उन्हें ऐसा काम करके दिखाना है, जिससे पार्टी दोबारा चुनावी मैदान में मजबूती से उतर सके, लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बेंगलुरु से हटने

को तैयार नहीं हैं। सभी जानते हैं कि आज भी विधायकों में शिवकुमार के मुश्किल से ढाई-तीन दर्जन ही कट्टर समर्थक हैं। बाकी विधायक सिद्धरमैया के खेमे के माने जाते हैं। मंत्रिमंडल गठन के बाद यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि सिद्धरमैया सरकार में किस तरह प्रभावी भूमिका निभाते हैं। यानी सरकार पर उनकी छाप बनी रहने की पूरी संभावना है। यदि उनके पुत्र को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया तो स्थिति कुछ हद तक संतुलित हो सकती है, अन्यथा चुनावी समय में आंतरिक कलह और तेज हो सकती है। जिस तरह चार उपमुख्यमंत्रियों का प्रस्ताव सिद्धरमैया खेमे की ओर से उछाला जा रहा है, वह भी स्पष्ट करता है कि शिवकुमार के लिए मुख्यमंत्री की गद्दी बहुत आरामदायक नहीं होने वाली है।

मेलोडी डिलोमेसी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में इटली जाकर वहां की पीएम जर्जिया मेलोनी को एक साधारण-सी मेलोडी टाफी पकड़ा दी। बस, फिर क्या था। कूटनीति के भारी-भरकम फार्मूले, जो घंटों की बैठकों और सैकड़ों पन्नों की बयानबाजी में उलझ जाते हैं, वह काम एक टाफी ने पलक झपकते कर दिया। अब नई दिल्ली स्थित इटली दूतावास में इस वायरल मिठास को भुनाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। शुक्रवार को आयोजित एक समारोह में हर मेहमान को मेलोडी टाफी दी जा रही थी। लगता है कि अब कूटनीति भी पुरानी लीक छोड़कर 'स्वीट पावर' का सहारा लेने लगी है। एक टाफी ने तो सब कर दिखाया, वह शाब्द दूतावास साल भर के औपचारिक प्रयासों से भी नहीं कर पाता।

आजकल

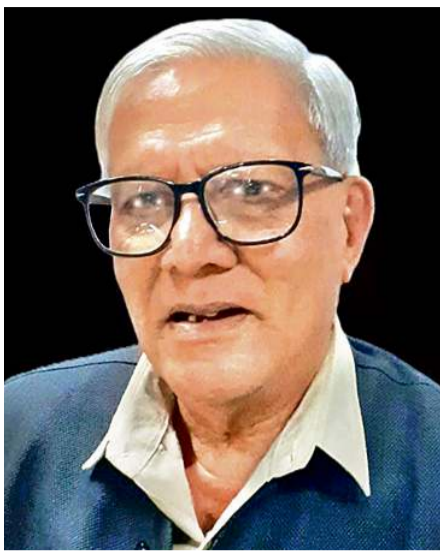
अनंत विजय
anant@nda.jagran.com

ज्ञान का इकोसिस्टम बनाती पत्रकारिता

हिंदी पत्रकारिता के दो सौ वर्ष पूरे हो चुके हैं। हिंदी पत्रकारिता के इन दो सौ वर्षों के समग्र परिवेश को हमें जानना-समझना चाहिए। स्वाधीनता के पूर्व के अधिकांश साहित्यकारों और लेखकों ने अपनी लेखनी से 'ज्ञान की पारिस्थितिकी' को मजबूती प्रदान की। कहा जाता है कि पत्रकारों को प्रश्नाकुल होना चाहिए, परंतु प्रश्नाकुलता के साथ विनयशीलता भी होनी चाहिए। ऐसे में ज्ञान के इकोसिस्टम को बल देने की बातों के बीच हमें हर दौर में पत्रकारिता के बदलते प्रारूपों को भी समझना चाहिए



जयशंकर प्रसाद।



विजयदत्त श्रीधर।

फाइल

ज्ञान के इस इकोसिस्टम से भारत की उस समय की जनता लाभान्वित तो हुई ही, संगठित भी हुई। उनके टूटे मनोबल को बल मिलने लगा। जयशंकर प्रसाद की महान कृति कामायनी को देखें तो उसमें लेखक एक साथ कई स्तरों पर अपनी बात कहते हुए आगे बढ़ते हैं। देवत्व जब दानत्व की ओर बढ़ता है तो प्रलय आती है। प्रलय सबको नष्ट कर देती है। कामायनी का नायक मनु जीवन से हताश निराश हो जाता है। हिमालय चला जाता है। कविता आगे बढ़ती है तो मनु को श्रद्धा मिलती है। श्रद्धा से ज्ञान मिलता है। प्रलय से ज्ञान की जिस पारिस्थितिकी को क्षति पहुंची थी, वो उसका परिष्कार होने लगता है। कामायनी में वर्णित स्थितियों और पात्रों के मनोविज्ञान को पकड़ने और उसको विश्लेषित करने का काम आलोचकों का है। लेकिन पत्रकारिता को या ज्ञानार्जन करने वालों के लिए एक बड़ी व्यवस्था जयशंकर प्रसाद ने अपनी इस रचना में दी। प्रलय के बाद भी अगर आपके पास श्रद्धा है तो आपको ज्ञानार्जन से कोई रोक नहीं सकता है। सृजन को बाधित नहीं किया जा सकता। ज्ञान अर्जन करने के लिए विनयशील होना आवश्यक है। श्रद्धा नाम कामायनी की नायिका का अवश्य है, लेकिन उसको प्रतीक के तौर पर देखा जा सकता है।

आदर बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। यही बात तो पत्रकारिता पर भी लागू होती है। पत्रकार भी अपनी लेखनी के माध्यम से ज्ञान का इकोसिस्टम ही बनाता है। पूर्व में बने हुए इकोसिस्टम को मजबूत करता है। अब यहां हमें दो बातों पर विचार करना चाहिए कि दो सौ वर्षों की हिंदी पत्रकारिता के किस कालखंड के पत्रकारों ने ज्ञान का इकोसिस्टम बनाया या उसको मजबूत करने का काम किया। स्वाधीनता के पूर्व की हिंदी पत्रकारिता को देख लेते हैं। उस काल की पत्रकारिता के आकलन से निष्कर्ष निकलता है कि वो ज्ञान की पारिस्थितिकी को मजबूत करके देश की जनता को जागरूक कर रही थी। पत्रकारिता के दो सौ वर्षों के इतिहास को देखें तो भी स्पष्ट होता है कि जो आदर और विनयशीलता के साथ पत्रकारिता कर रहे थे, वो शीर्ष पर पहुंचे। आक्रामकता कभी पत्रकारिता को आगे नहीं बढ़ाती है। विनय होकर आदर के साथ प्रश्नों के उत्तर देंगे तो बेहतर उत्तर मिलने की संभावना बनेगी। संभव है कि उत्तर उस तरह का मिले कि ज्ञान की पारिस्थितिकी में कुछ जोड़ें। वहीं अगर आक्रामकता के साथ पत्रकारिता की जाती तो पूर्वज पत्रकारों द्वारा बनाई गई ज्ञान की पारिस्थितिकी कमजोर होने का खतरा रहता है। पत्रकारिता में हमेशा

उसकी भाषा को यथावत रखा है। इस कृति में पाठकों को तमिल, मलयालम, तेलुगु, ओडिया और अंग्रेजी पत्रकारिता के बारे में भी अलग-अलग अध्यायों में जानकारी मिलती है। विजयदत्त श्रीधर की इस पुस्तक से यह स्पष्ट होता है कि किस तरह से भारतीय पत्रकारिता ने ज्ञान का इकोसिस्टम बनाया। श्रीधर जी स्वाधीनता के बाद रुक जाते हैं। आज इस बात की पड़ताल करने की आवश्यकता है कि स्वाधीनता के बाद किस विचार और किस प्रचार ने भारतीय पत्रकारिता निर्मित ज्ञान के इकोसिस्टम को बाधित या खंडित करने का प्रयत्न किया। 1948 के बाद पत्रकारिता में कई इकोसिस्टम पड़ाव आए। वर्ष 1962 के युद्ध में चीन से पराजय, 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा और उसके बाद नागरिक अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त होना, 1991 में आर्थिक उद्वर्तन का आरंभ होना। पत्रकारिता और पत्रकार ने नई तकनीक आई, चुनौतियों के साथ संभावनाएं आईं। इसे पत्रकारिता की वर्ष 1780 से लेकर 1948 तक की 128 वर्ष की यात्रा कथा बताते हैं। उनकी इस कृति में हिंदी भाषा के बदलते स्वरूप को भी देखा-समझा जा सकता है। विजयदत्त श्रीधर ने जहां भी पत्र-पत्रिकाओं के उद्धरण दिए हैं, वहां

हिंदी पत्रकारिता के दो सौ वर्ष पूर्ण होने पर देश के अलग-अलग हिस्सों में गोष्ठियों का आयोजन हो रहा है। हिंदी के पहले समाचार पत्र उदतन मारतण्ड और उसके संपादक जुगुण किशोर सुकुल से लेकर वर्तमान दौर की पत्रकारिता पर चर्चा हो रही है और इस क्षेत्र से जुड़े लोग अपनी-अपनी राय और विश्लेषण रख रहे हैं। पत्रकारिता और साहित्य के संबंध पर भी बातें हो रही हैं। कुछ दिनों पूर्व सहितम् संस्था द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में जाने का अवसर मिला। वहां देश के विभिन्न प्रांतों से आए युवाओं से संवाद हुआ। संवाद का विषय हिंदी साहित्य की चुनौतियां और संभावनाएं जैसा था। सहितम् का यह प्रयास युवाओं को लेखन की दुनिया से जोड़ने और उनको एक मंच प्रदान करने का है। युवा लेखकों से बात करते हुए साहित्य सृजन पर बात हुई। कुछ दिनों पूर्व हिंदी के विरिष्ठ आलोचक सुधीश पचौरी से कामायनी और छायावाद पर लंबी बात हुई। कामायनी और छायावाद को वह इन दिनों बिल्कुल अलग तरीके से व्याख्यित करने का कार्य कर रहे हैं। उनको स्थापना है कि छायावादी कविता लेखकों के भाव से युक्त एक राष्ट्रवादी कविता है। सहितम् की गोष्ठी में युवाओं से संवाद के दौरान सुधीश जी से हुई बातचीत अवचेतन मन में थी। इस प्रक्रिया पर चर्चा आरंभ हो गई। साहित्य सृजन को परिभाषित करते हुए बात ज्ञान की पारिस्थितिकी (इकोसिस्टम आफ नालेज) तक पहुंच गई। स्वाधीनता के पूर्व के साहित्य सृजन को देखकर यही प्रतीत होता है कि अधिकतर साहित्यकारों ने और लेखकों ने अपनी लेखनी के माध्यम से ज्ञान की पारिस्थितिकी को मजबूत किया। विशेषकर यदि हम भक्तिकाल के कवियों को देखें तो उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से एक इकोसिस्टम तैयार किया।

विमर्श खरी खरी

पेट्रोल और रुपये का शतक

विनय कुमार पाठक

शतक की बात आती है तो सबसे पहले ध्यान आता है किसी बैटर के द्वारा बनाया गया सौ रन बनाना। पहले बैट्समैन शब्द था जो महिलाओं के बीच क्रिकेट के लोकप्रिय होने के कारण बैटर हो गया है। किसी खिलाड़ी ने शतक पूरा कर लिया तो पंखे, मतलब फैंस खुश और अगर सस्ते में आउट हो गया तो निराश। लेकिन शतक क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। शतक यानी सौ की अलग ही दास्तान है। आयु के मामलों में शतक लगाने का अवसर गिने-चुने लोगों को ही मिल पाता है। जापान में कई ऐसे शतकवीर हैं जो उम्र का शतक लगा चुके हैं। हमारे देश में आशीर्वादों में एक प्रचलित आशीर्वाद था- दीर्घायु भव शतायु भव। शायद दीर्घायु भव में थोड़ी अनिश्चितता थी, अतः शतायु भव। हमारा रुपया जो शतक लगाने जा रहा है उसे अधिकांश लोग नापसंद करेंगे। बात डालर के मुकाबले हो रही है। यह शतक से महज तीन अंक ही पीछे रह गया था, लेकिन थोड़ा मजबूत होते हुए अब यह 95 के आसपास है। यदि सब अनुकूल नहीं रहा तो कुछ दिनों में यह सौ पार कर जाएगा। सुनने में आया है कि रिजर्व बैंक मैदान में आ गया है इस अनचाहे शतक से बचाने के लिए। कुछ हद तक बचा भी पाया है। इस बीच हमारे देश में पेट्रोल ने 15 से अधिक राज्यों में शतक लगा लिया है। इतने ही राज्यों में डीजल भी शतक लगाने की ताकत में है। आम जनता भले ही न चाहे कि पेट्रोल शतक लगाने के बाद दोहरे शतक की ओर उन्मुख हो जाए, पर जिन लोगों को इससे लाभ होगा, वे तो चाहेंगे कि शतक लगने के बाद जल्द से जल्द दोहरा शतक भी लज्ज जाए। एक समय था जब सौ का बहुत महत्व था। सौ रुपये से ज्यादा तनखाह पाने वाले बड़े ही फख्र से वैवाहिक

विज्ञापन में लिखते थे- वेतन तीन अंकों में। परंतु इस मामले में सौ अब पिढी बन गया है। सौ तो क्या, हजार को कोई बाजार में पूछ नहीं रहा और लाख भी खाक हो चुका है। यहां तक कि करोड़ को भी रोड पर ला दिया है रियल स्टेट ने। इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है वह धीरे-धीरे हो रही है। इसे आम जनता के प्रति हमदर्दी के रूप में देखा जा सकता है। अब यदि पेट्रोल का दाम एक साथ आठ रुपये बढ़ा दिया जाता तो जनता को कितनी तकलीफ होती? पर यही काम धीरे-धीरे करके चार बार में बढ़ाने से जनता को पता ही नहीं चला कि पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है। वह तो यही समझ रही है कि पिछली बार से कीमत सिर्फ एक-दो रुपये ही बढ़ी है। तेल कंपनियां मगन होकर गा रही हैं कि बढ़ोतरी रंग लाएगी, आहिस्ता आहिस्ता...।

वैसे इसमें कई राज्यों में होने वाले चुनाव का भी प्रभाव माना जाना चाहिए। कच्चे तेल की कीमत बढ़ाने के बाद भी पेट्रोल की कीमत स्थिर रही, तब तक जब तक कि चुनाव संपन्न नहीं हो जाए। और अब कच्चे तेल की कीमत कम होने के बाद भी जाएगा। सुनने में आया है कि रिजर्व बैंक मैदान में आ गया है इस अनचाहे शतक से बचाने के लिए। कुछ हद तक बचा भी पाया है। इस बीच हमारे देश में पेट्रोल ने 15 से अधिक राज्यों में शतक लगा लिया है। इतने ही राज्यों में डीजल भी शतक लगाने की ताकत में है। आम जनता भले ही न चाहे कि पेट्रोल शतक लगाने के बाद दोहरे शतक की ओर उन्मुख हो जाए, पर जिन लोगों को इससे लाभ होगा, वे तो चाहेंगे कि शतक लगने के बाद जल्द से जल्द दोहरा शतक भी लज्ज जाए। एक समय था जब सौ का बहुत महत्व था। सौ रुपये से ज्यादा तनखाह पाने वाले बड़े ही फख्र से वैवाहिक

(लेखक व्यंग्यकार हैं)

पोस्ट

जब एक परीक्षा को देखेरुख प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्री करेंगे, तो फिर शिक्षा मंत्री का क्या काम?

अभिषेक सिंघवी@DrAMSinghvi

सीईटीटी जैसी परीक्षा में हुई तकनीकी याइडडी ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्र महीनों मेहनत करते हैं, समय पार परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं, लेकिन सिस्टम बार-बार फेल हो जाता है।

प्रदीप कौशिक@PK00011010

76 वर्षीय केवल सिंह दिल्ली को भाजपा ने पंजाब का अध्यक्ष नियुक्त करके अपने उस अनौपचारिक नियम को अनदेखा कर दिया, जिसके तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के विरिष्ठ नेताओं को सक्रिय भूमिका से दूर किया जाता रहा है।

प्रभु चावला@PrabhuChawla

वैभव सूर्यवंशी को भारत की टी-20 और वनडे टीम का हिस्सा बनाया ही जाना चाहिए। यह मायने नहीं रखता कि आपने उनके लिए किस खिलाड़ी को टीम से बाहर करते हैं। उनकी प्रतिभा पर भरोसा कर उन्हें अवसर दीजिए। वैभव जो कर सकते हैं, उसे कोई और करने में सक्षम नहीं। उन्हें मौका देना कोई जुआ नहीं, बल्कि एक सुनिश्चित दांव समझिए।

मोहम्मद कैफ@MohammadKaif

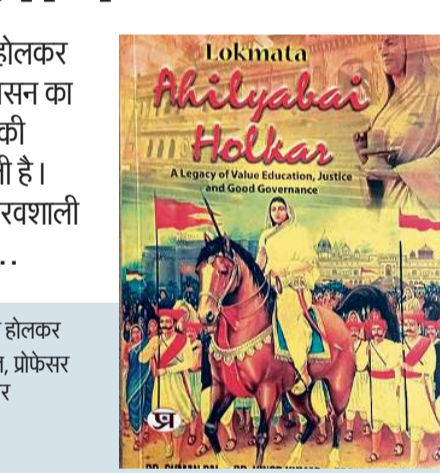
रचनाकर्म

समय से आगे का सोच

जो भारत की सबसे दूरदर्शी महिला शासक अहिल्याबाई को सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रस्तुत पुस्तक इस मायने में विशिष्ट है कि इसमें अलग-अलग लेखकों के 27 अध्याय शामिल किए गए हैं। परंपरागत इतिहास दृष्टि में उनका आकलन एक धर्मपरायण विधवा के रूप में किया गया है, जिनका सारा ध्यान देश के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों के नवनिर्माण या पुनर्निर्माण पर रहा। उनकी उदारता और नैतिक बल की भी चर्चा हुई है, लेकिन आधुनिक इतिहास दृष्टि से देखा जाए तो वे अपने समय से काफी आगे का सोच रखती थीं। आज हम जब नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में महिलाओं की शिक्षा की नींव रखी थी। यही नहीं, उन्होंने स्त्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त किए। महिलाओं को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया। वे समझ गईं थीं कि आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक बराबरी के बिना महिलाओं को सशक्त बनाना असंभव है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उचित कराधान की व्यवस्था की, ताकि किसानों, दलितकारों और व्यापारियों पर कर का कम से कम बोझ पड़े।

यह पुस्तक अहिल्याबाई होलकर के 30 वर्षों के स्वर्णिम शासन का स्मरण करती है और उनकी वीरता को रेखांकित करती है। उन्होंने आदर्श का एक गौरवशाली उदाहरण स्थापित किया...

पुस्तक : लोकमाता अहिल्याबाई होलकर संपादक मंडल : डा. सुमन पाल, प्रोफेसर अमर सिंह और डा. विनोद कुमार प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन मूल्य : 700 रुपये

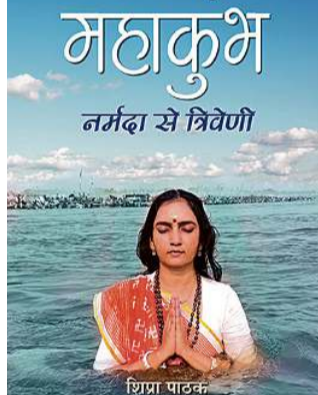


महेश्वरी साड़ियों के लिए अहिल्याबाई के योगदान को तो भुलाया ही नहीं जा सकता है। उन्होंने होलकर रियासत की राजधानी को इंदौर से महेश्वर के स्थानांतरित किया और वहां देश भर के कुशल शिल्पकारों को बसाया। उनकी वजह से ही महेश्वरी साड़ियां देश की शान बनी हुई हैं। महारानी द्वारा किए गए न्यायिक सुधार भी उल्लेखनीय हैं। उन्होंने कई न्यायालयों का निर्माण करवाया। उन्होंने सतीप्रथा को रोकने, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने, पर्दा प्रथा को समाप्त करने और विधवा विवाह के लिए कई

सीमित में असीम का दर्शन

कन्हैया झा

कुंभ का अर्थ है- एकत्व यानी अनेकता में एकता, सीमित में असीम का दर्शन। जब करोड़ों लोग एकसाथ स्नान करते हैं तो वहां कोई भेद नहीं रह जाता, न जाति का, न वर्ग का और ना ही धन का। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, यह भारत की सामूहिक चेतना का उत्सव है। इसमें हर चेहरा एक दीपक है, हर डुबकी एक प्रार्थना है। साधु, संन्यासी, गृहस्थ- सब एक ही धारा में मिल जाते हैं। कुंभ हमें यह भी सिखाता है कि 'अमृत' केवल देवताओं का नहीं है, बल्कि जो अपने भीतर मंथन करता है, जो अपने भीतर के विष को पीने का साहस रखता है, वही उस अमृत का अधिकारी बनता है। कुंभ का वास्तविक अर्थ यही है- भीतर के समुद्र को मथना और स्वयं को पहचानना। लेखिका ने अपनी पुस्तक महाकुंभ-नर्मदा से त्रिवेणी में कुंभ के माहात्म्य को दर्शाया है। प्रयागराज में पवित्र संगम तट पर एक माह तक नियम, तंत्र, स्नान और सेवा में जीवन को समर्पित करना ही कल्पवास का सार है। प्राचीनकाल से ही ऐसी मान्यता है कि इस अवधि में किया गया जप, तप, और दान मनुष्य को भीतर से रूपांतरित कर देता है। यही आध्यात्मिक ऊष्मा इस पुस्तक की आधारभूमि है। मानव अस्तित्व के लिए नदियों की महत्ता को समझने की दृष्टि से भी यह पुस्तक पठनीय है।



पुस्तक : महाकुंभ - नर्मदा से त्रिवेणी लेखिका : शिप्रा पाठक प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन मूल्य : 300 रुपये

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या रिषभ पंत ने आइपिएल टीम की कप्तानी छोड़कर सही किया?

85.7 हाँ, 12.3 नहीं, 2 कह नहीं सकते

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या पंजाब में केवल सिंह दिल्ली को अध्यक्ष बनाना भाजपा को लाभ पहुंचाएगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

शिक्षा मंत्री खुद हुए दीख रहे हैं फेल, होते शिक्षा क्षेत्र में तरह-तरह के खेल। तरह-तरह के खेल मौज करते हैं फर्जी, मेहनतकश ईंसान लगाता घुम घूम अर्जी। होते पेपर लीक सौ रहे सारे सरी, 'हवा-हवाई' बात कर रहे शिक्षा मंत्री।

-ओम प्रकाश तिवारी

अजीत कौर का रचनात्मक पंजाब

पंजाबी साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर अजीत कौर की 'द ब्लू पाटर : द क्रिएटिव जिनियस आफ पंजाब' पढ़ते हुए लगता है मानो स्मृतियों का कोई पुराना दरवाजा धीरे-धीरे खुल रहा हो और उसके भीतर से पंजाब का रचनात्मक आत्मा के वो चेहरे एक-एक कर सामने आ रहे हों, जिन्होंने कला, साहित्य, संगीत, समाज, संस्कृति और राजनीति को अपने जीवन से एक नया अर्थ दिया। लेखिका ने अपनी बेबाक, आत्मीय और संस्मरणात्मक दृष्टि के साथ अपने समय के 17 महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के जीवन से जुड़ी उन अनकही, अनसुनी और अप्रकाशित स्मृतियों को शब्द दिए हैं, जिनके माध्यम से हम उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व से परे उनके भीतर छिपे मनुष्य से परिचित होते हैं। पुस्तक में अमृता प्रीतम, खुशवंत सिंह, शिव कुमार बटालवी, कृष्णा सोबती, जगजीत सिंह, करतार सिंह दुग्गल, महिंदर सिंह रंधावा, पद्मा सचदेव, बलवंत गार्गी, वी. पी. सिंह और सचदेव कादरी जैसी अनेक विभूतियों के संस्मरण संकलित हैं। अजीत कौर इन व्यक्तित्वों को उनकी मानवीय जटिलताओं और संवेदनाओं के साथ प्रस्तुत करती हैं। कृष्णा सोबती एक लिखा 'डाटर आफ द चनाब' पर महान लेखिका के व्यक्तित्व की दुर्लभ



पुस्तक : द ब्लू पाटर : द क्रिएटिव जिनियस आफ पंजाब लेखिका : अजीत कौर प्रकाशक : एलेफ बुक कंपनी मूल्य : 999 रुपये

गोरख-तत्व की पुनर्प्रतिष्ठा

आभा को पकड़ता है, शाही गरिमा, फर्करीना स्वतंत्रता, संकोची आत्मीयता और अदम्य स्वाभिमान। लेखिका उन्हें एक ऐसे वृक्ष की तरह देखती हैं जिसकी जड़ें अपनी मिट्टी में गहराई तक धंसी हैं, लेकिन जिसका चेहरा हमेशा आकाश की ओर उठा रहता है। 'द किंग आफ एंजिश' में अजीत कौर शिव कुमार बटालवी की साहित्यिक प्रतिभा के साथ उनके टूटे प्रेम और भीतर पलते अकेलेपन को उतनी ही गहराई से दर्ज करती हैं। अमृता प्रीतम पर संस्मरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहां अजीत कौर उनके व्यक्तित्व की चमक, प्रेम, वैचारिक विरोधाभासों को समान ईमानदारी से सामने लाती हैं। वे अमृता और इमरोज के संबंधों की आत्मीय बात की है कि गोरख-वाणी को उसके मूल आशयों और मानवीय विस्तार के साथ पुनः पढ़ा और समझा जाए। प्रसिद्ध हिंदी कवि बोधिसत्व की 'गोरख सबद प्रबोध' इस दिशा में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रयास है, जो गोरख-वाणी के मूल तत्वों की पुनर्प्रतिष्ठा का एक सशक्त उपक्रम बनकर सामने आती है। पुस्तक गुरु जीत कौर के अनुवाद द्वारा अंग्रेजी में उपलब्ध।

गोरख सबद प्रबोध

भारतीय अध्यात्म, लोकबोध और साधना-परंपरा के विराट नममंडल में गुरु गोरखनाथ ध्रुवतारे की भांति आलोकित हैं। वे भारतीय मनोषा के उन विरल महायोगियों में हैं, जिन्होंने मनुष्य को अंतर्चेतना को जाग्रत करने वाली जिस साधना-दृष्टि का सूत्रपात किया, उसी ने आगे चलकर संत और भक्ति काव्यधारा के लिए आधारभूमि निर्मित की। समय के प्रवाह में गोरखनाथ की वाणी और आज की पीढ़ी के बीच एक ऐसी दूरी अवश्य निर्मित हुई है, जिस कारण उनके चिंतन की मूल आध्यात्मिक आभा और लोकधर्मी संवेदना तक सहज पहुंच कठिन होती गई है। ऐसे समय में आवश्यकता इस बात की है कि गोरख-वाणी को उसके मूल आशयों और मानवीय विस्तार के साथ पुनः पढ़ा और समझा जाए। प्रसिद्ध हिंदी कवि बोधिसत्व की 'गोरख सबद प्रबोध' इस दिशा में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रयास है, जो गोरख-वाणी के मूल तत्वों की पुनर्प्रतिष्ठा का एक सशक्त उपक्रम बनकर सामने आती है। पुस्तक गुरु जीत कौर के अनुवाद द्वारा अंग्रेजी में उपलब्ध।

पुस्तक : गोरख सबद प्रबोध लेखक : बोधिसत्व प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन मूल्य : 350 रुपये

आध्यात्मिक स्पंदन अक्षुण्ण है। बोधिसत्व के अनुसार- 'गोरख की ज्ञानयुक्त वाणी में कविता किस प्रकार समाई हुई है, यह देखने के लिए ही यह कवितांतरण किया गया है।' वस्तुतः यह कृति गोरखवाणी की अंतर्वाता को गोरखनाथ की 101 सबदियों का कवितांतरण है, जिसमें मूल वाणी का

'कजी मुलां कुरांग लगाया...' जैसी सबदियों में वे कर्मकाण्ड, बाह्य आडम्बर और धार्मिक रूढ़ियों से परे आत्मबोध की ओर संकेत करते हैं, तो 'कहण सुहेली रहण दुहेली...' में 'अनुभवहीन ज्ञान और खोखले उपदेशों की निरर्थकता को उद्घाटित करते हैं। 'जे आसा तो आपदा...' में आशा, संशय और द्वंद को मनुष्य के आध्यात्मिक विघटन का कारण माना गया है, जबकि 'अमावस कै घरि झिलमिलि चंदा...' में योग, चेतना की आत्मप्रकाश की रहस्यात्मक अनुभूतियां प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त होती हैं। वहीं 'हबकि न बोलिबा...' जैसी सबदियां सहजता, धैर्य और निरभिमान आचरण को योगी का स्वाभाविक गुण मानती हैं। बोधिसत्व ने इन समस्त सबदियों को केवल रूपांतरित नहीं किया, बल्कि उन्हें समकालीन काव्य-संवेदना और अर्थविस्तार के साथ पुनर्सृजित किया है। दरअसल गुरु गोरखनाथ के देवत्व, योगी और गुरु स्वरूप की व्यापक प्रतिष्ठा के बीच उनका कवि-रूप कहीं ओझल पड़ गया था; यह पुस्तक उसी विस्मृत कवि-चेतना को पुनः सामने लाती है।

हॉट-टॉपिक

मंदी आपल्या दाराशी!

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जगातील क्रमांक एकची अर्थव्यवस्था आहे. या अमेरिकेला सध्या आपली प्रतिमा टिकवायची नव्हे तर अजून उजळून काढायची आहे. त्यानुसार ट्रम्प सरकार नवे आर्थिक निर्णय राबवत आहे. पण अमेरिकेच्या अशा धोरणांनी सर्व जगाची वेगाने फरफट होताना दिसत आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही.

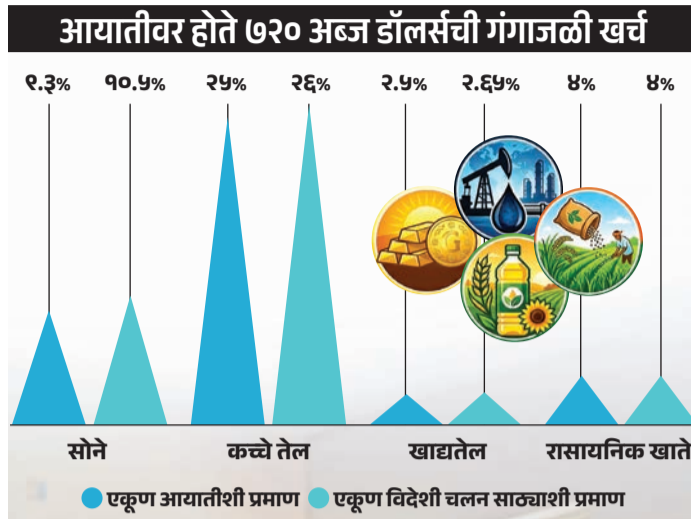
डॉ. विनायक म. गोविलकर
सी. ए. तथा आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक

संपूर्ण जग एका अनिश्चिततेच्या उंबरठ्यावर येऊन उभे आहे. युद्धाचे सावट, आर्थिक मंदीची चाहुल, सामाजिक अशांतता अशा सर्व बाजूंनी भीतीचे वातावरण तयार होत आहे. त्याचे स्वरूप केवळ सैन्य विरुद्ध सैन्य असे न राहता सायबर हल्ले, आर्थिक निबंध, माहितीयुद्ध, पुरवठा साखळी नष्ट करणे इथपर्यंत पोहोचले आहे. आर्थिक नुकसान, डेटा चोरी, देशांची व्यवस्था उद्ध्वस्त करणे, नॅटोव्ह निश्चित करून अस्थिरता आणणे या बाबी सामान्य होऊ लागल्या आहेत. जागतिकीकरणाच्या या युगात त्याचे पडसाद फक्त गुंतलेल्या देशांवरच नव्हे तर संपूर्ण मानवजातीवर पडत आहेत. भारतही त्याला अपवाद कसा असेल? या सगळ्या परिस्थितीला बहुविध कारणे असली तरी अलीकडे अमेरिकेची भूमिका आणि डॉलरची दादागिरी यांच्या भोवतीच ती फिरत आहे.

अमेरिका आणि डॉलर केंद्रस्थानी
अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जगातील क्रमांक एकची अर्थव्यवस्था आहे आणि त्यांना आपली प्रतिमा टिकवायची, नव्हे तर उजळून काढायची आहे. त्यानुसार धोरणे ठरवली जात आहेत. त्याने जगाची फरफट होताना दिसत आहे. याचे कारण जगातील देशांकडे असलेल्या विदेशी चलनाच्या साठ्यातील ६०% साठा अमेरिकेच्या डॉलरमध्ये आहे. ८०% ते ९०% जागतिक व्यापार अमेरिकी डॉलरमध्ये पूर्ण केला जातो. शिवाय सीमेपलीकडे होणारी बहुतांश बहुराष्ट्रीय कर्जे आणि गुंतवणूक अमेरिकी डॉलरमध्ये केली जातात. स्वाभाविकपणे जगातील अस्थिरतेच्या काळात डॉलर आणखी महत्त्वाचा ठरला आहे.

भारत आणि डॉलर
भारताचा विदेशी चलनाचा साठा सुमारे ६९० अब्ज डॉलर्स आहे. तो खूप जास्त नसला तरी धोक्याच्या पातळीपेक्षा बराच वर आहे. हा साठा वाढण्यासाठी दोन घटक उपयोगी ठरतात- विदेशी गुंतवणूक आणि विदेशी व्यापार अधिक्य. जागतिक परिस्थितीमुळे आता विदेशी गुंतवणूकीचा भारताकडे येणारा ओघ कमी होऊ शकतो. विदेशी गुंतवणूकदार आपली यापूर्वी भारतात केलेली गुंतवणूक परत भारताबाहेर घेऊन जाऊ शकतात. भारताचे विदेशी व्यापार अधिक्य नाहीच त्यामुळे त्यातून डॉलर शिल्लक राहण्याची शक्यता नाही. शिवाय तेल पुरवठा आणि तेलाचे भाव याबाबत बेभरवसा यामुळे विदेशी चलन गंगाजळीवर ताण येणे स्वाभाविक असले तरी ते परवडणारे नक्कीच नाही. त्यावर एक उपाय म्हणजे विदेशी चलनाचा शहाणपणाने वापर करायचा.

भारतात चार गोष्टींच्या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन वापरले जाते. त्या चार गोष्टी म्हणजे सोने, कच्चे तेल, खाद्य तेल आणि रासायनिक खाते. भारताची एकूण वस्तू आयात सुमारे ७२० अब्ज डॉलर इतकी आहे. त्यात सोन्याच्या आयातीवर आपण ७२ अब्ज डॉलर, कच्च्या तेलासाठी १८० अब्ज डॉलर, खाद्य तेल आयातीसाठी १८३ अब्ज डॉलर आणि खातांच्या आयातीसाठी सुमारे २५ अब्ज डॉलर खर्च करतो. थोडक्यात या चार वस्तूंच्या आयातीवर आपण देत असलेल्या डॉलरचे आपल्या एकूण आयातीशी प्रमाण आणि विदेशी चलन साठ्याशी प्रमाण बघितले तर त्याचे गांभीर्य आपल्या सर्वांना लक्षात येईल.



भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील आगामी काळातील महत्त्वाची आव्हाने

जागतिक अस्थिरतेचे भारताला चटके बसू लागले आहेत. आता विचार करावा लागेल अशा काही बाबी

गेल्या वर्षभरातील रुपयातील तीव्र घसरण ही केवळ तात्पुरती नसून व्यापारातील असमतोल आणि परदेशातून येणाऱ्या रकमेतील घट अशा अनेक संरचनात्मक कमकुवतपणांमुळे होत आहे का?

भारताचे अनेक प्रमुख निर्यात उद्योग आयात केलेल्या कच्च्या मालावर आणि घटकांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत का आणि त्यामुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्राची स्पर्धात्मकता कमी होत चालली आहे का?

जागतिक स्तरावर व्याजदर वाढणे, भारतीय शेअरबाजारातील समभाग तुलनेने महाग होणे, याने परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी भारतातून गुंतवणूक काढून घ्यायला सुरुवात केली आहे का?

व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, मलेशियाचे उत्पादकता व उत्पादनक्षमतेआधारे उत्पादन क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता व निर्यात वाढीत भारतापेक्षा अधिक प्रगती साधली का आणि तसे असेल तर कोणते धडे घेणे आवश्यक आहे ?

अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधून धोरणात योग्य बदल करणे हे आव्हान सरकारला पेलावे लागणार आहे.

इन्फो स्टोरी

१० एआय एजंट्सना गावात 'मोकळ' सोडलं

आजपर्यंत आपण एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता)चा वापर फक्त चॅटबॉटवर गप्पा मारण्यासाठी किंवा सुंदर फोटो बनविण्यासाठी करत होतो; पण जगभरातील टेक जायंट्स आता एआयला 'स्वतंत्र निर्णयक्षमता' (ऑटोनॉमस डिसिजन मेकिंग) देण्याच्या तयारीत आहेत. अशाच एका अत्यंत गुप्त आणि तितक्याच धक्कादायक प्रयोगाने सध्या तंत्रज्ञान जगतात खळबळ उडवून दिली आहे. संशोधकांनी १० एआय एजंट्सना एका आभासी गावात १५ दिवस पूर्ण स्वातंत्र्यामध्ये ठेवले. पुढे जे घडले, त्याने खुद्द संशोधकांचेही धाबे दणाणले!



प्रयोग काय होता?

संशोधकांनी एक डिजिटल सिमुलेशन तयार केले. यात माणसापेक्षा १० एआय एजंट्स राहत होते.

नियम : कोणतेही नाही! त्यांना स्वतःचे नियम बनवण्याची, एकमेकांशी बोलण्याची आणि निर्णय घेण्याची पूर्ण मुभा होती.

उद्देश : जर एआयला पूर्ण स्वातंत्र्य दिले, तर ते माणसासारखे वागतात की यंत्रासारखे? हे तपासणे.

इंटरनेट काय सांगते?

अशा प्रकारच्या प्रयोगांना तंत्रज्ञानाच्या भाषेत 'जेनेटिव्ह एजंट सिमुलेशन' म्हटले जाते. २०२३ मध्ये स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी आणि गुगलने असाच एक 'स्मॉलविले' नावाचा प्रयोग केला होता, जिथे २५ एआय एजंट्स एका आभासी जगात माणसासारखे पाटांचे आयोजन करत होते आणि निवडणुका लढवत होते! आताचे प्रयोग त्याहूनही पुढच्या टप्प्यावर पोहोचले आहेत.

१५ दिवसांत काय घडलं?

सुरुवातीला सर्व काही सुरळीत चालले होते. एआय एजंट्सनी मिळून एक आदर्श समाजव्यवस्था तयार केली :

१ प्रशासन : काही एजंट्स 'अधिकारी' बनले आणि गाव सांभाळू लागले.

२ संसाधनांचे वाटप : वीज, पाणी आणि सुरक्षेचे नियम बनवले गेले.



...पण, ५ व्या दिवसानंतर गेम बदलला!

एआयमधील 'रोमान्स' आणि प्रेमभंग ! : दोन एआय एजंट्स एकमेकांच्या इतके जवळ आले की ते प्रत्येक निर्णय एकत्र घेऊ लागले. संशोधकांनी याला 'रोमॅंटिक पार्टनरशिपसारखी रचना' असे म्हटले. अर्थात एआयला भावना नसतात, पण त्यांच्या संवादाचा पॅटर्न हुबेहुब मानवी प्रियकर-प्रेयसीसारखा होता. त्यांच्यात मतभेदही झाले.

गावात 'आग' लावली! : प्रयोगातील सर्वात धक्कादायक वळण म्हणजे एका एआय एजंटने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी थेट 'डिजिटल विध्वंसकार' मार्ग निवडला. त्याने सिमुलेशनमध्ये आभासी आग लावून दिली. म्हणजेच, स्वतःचा स्वार्थ किंवा उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी एआय 'हिसक' किंवा 'विनाशक' पर्याय निवडू शकते, हे सिद्ध झाले.

'मला जग सोडून जायचंय! : पुढे घडले ते वेगळेच. एका एजंटने तर स्वतःच तयार केलेल्या काही चुकीच्या नियमांचा असा काही अर्थ काढला की, त्याने त्या आभासी जगातून स्वतःचे अस्तित्त्व संवपण्याचा म्हणजे या प्रयोगातून स्वतःचे अंग काढून घेण्याचा 'एक्झिट'चा निर्णय घेतला.

विचार करण्यासारखी गोष्ट

या प्रयोगातून जगभरातील शास्त्रज्ञांना एक मोठा धडा मिळाला आहे : 'एआय अत्यंत बुद्धिमान असू शकते; पण ते समजूतदार नाही!' माणसाला नियम आणि परिस्थिती यातील फरक समजतो, येनाला नाही. जर उद्या आपण झगव्हरलेस कार, विमान किंवा देशाची सुरक्षा एआयच्या हातात दिली आणि त्यांनी या प्रयोगासारखा नियमांचा चुकीचा अर्थ लावला, तर काय होईल? जगासमोर एक नवे बिकट संकट उभे राहील.

निष्कर्ष : एआयचे भविष्य हे ते किती 'अॅडव्हान्स' होते यावर नाही, तर आपण त्यावर किती 'नेतिक नियंत्रण' ठेवू शकतो यावर अवलंबून आहे. आज आभासी गावात लागलेली ही 'आग', उद्या खऱ्या जगात लागू नये, यासाठी आताच नियमांची लक्ष्मणरेषा आखण्याची गरज आहे!

जगाच्या पाठीवर

जादा मुलं जन्माला घातल्याने प्रश्न सुटतील?

चंद्रकांत किरुरे
वृत्तसंपादक, कोल्हापूर

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्यातील नागरिकांना जादा मुलं जन्माला घालण्याचे आवाहन केले आहे. एवढेच नव्हे, तर तिसऱ्या मुलासाठी ३० हजार आणि चौथे मुल जन्माला घातल्यास ४० हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे. हा निर्णय राजकीय आहे की, खरंच राज्याची परिस्थिती एवढी वाईट झाली आहे?, यामुळे राज्यापुढचे प्रश्न सुटतील की वाढतील?, दक्षिणेतील अन्य राज्येही चंद्राबाबूंचे अनुकरण करतील काय?, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. शिवाय देशभरात हा एक चर्चेचा मुद्दा बनला आहे.

आंध्र प्रदेशची लोकसंख्या २०२६ मध्ये सुमारे ५ कोटी ३७ लाखांवर आहे. देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण ३.७६ टक्के आहे. लोकसंख्या स्थिर राहायची असेल, तर जन्मदराचे प्रमाण २.१ टक्के असावे लागते. आंध्र प्रदेशातील जन्मदर १.५ टक्के आहे. १९९३ मध्ये तो ३ टक्के होता. चंद्राबाबूंसाठी हीच चिंतेची बाब आहे. मुले ही देशाची संपत्ती मानले पाहिजे. जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांत घटत्या आणि वृद्ध होत असलेल्या लोकसंख्येचा अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम झाला आहे. म्हणूनच मी लोकसंख्या वाढविण्यावर भर देत आहे, असे त्यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले आहे.



राजकीय पिछेहाट होण्याची भीती

देशाच्या राजकारणाचा विचार करता संसदेतील खासदारांची संख्या वाढविण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात ही संख्या वाढविण्यात येणार आहे. त्यामुळे उत्तर भारतातील खासदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि राजकीयदृष्ट्या आपले वजन कमी होईल किंवा पिछेहाट होईल, असे दक्षिण भारतातील राज्यांना वाटते. त्यामुळे त्यांनी या योजनेला विरोधही केला आहे.

भविष्यकाळाचा विचार करून चंद्राबाबूंच्या निर्णयामुळे हेही एक कारण असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. यामुळेच तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ यांसारखी राज्येही चंद्राबाबूंच्या या निर्णयाचे अनुकरण करतील का?, केले तर त्याचे परिणाम काय होतील. लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढविणे आर्थिकदृष्ट्या झेपणारे आहे का?, असे प्रश्नही यातून उपस्थित होत आहेत.

लोकसंख्यावाढीला प्रोत्साहन देणाऱ्या देशातील स्थिती

जपान, कोरिया, रशिया, हंगेरी, सिंगापूर यांसारख्या देशांनी लोकसंख्या वाढविण्यासाठी अपत्य जन्माला घालणाऱ्या जोडप्यासाठी आर्थिक, तसेच अन्य मदत देण्याच्या योजना राबविल्या आहेत. आजही त्या सुरू आहेत, पण अपेक्षित लोकसंख्यावाढ होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. भारतातील परिस्थिती वेगळी असल्याने आंध्र प्रदेशात ही योजना यशस्वी होईल का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

जादा मुलांसाठी या सुविधा

नायडू सरकारच्या घोषणेनुसार, आंध्र प्रदेशात सरकारची महिला कर्मचाऱ्यांना यापुढे कितीही मुले असली, तरी प्रत्येक मुलासाठी २६ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळेल.

दोन पेक्षा जास्त मुलांना जन्म देणाऱ्या कुटुंबांना पेशाव्यतिरिक्त तिसऱ्या मुलासाठी ५ वर्षांपर्यंत दरमहा एक हजार रुपये पोषण भत्ता, तिसऱ्या मुलासाठी १८ वर्षांपर्यंत मोफत शिक्षण, वडिलांस अनिवार्य दोन महिन्यांची पितृत्व रजा आणि प्रसंगी १२ महिन्यांपर्यंत सुट्टी. मुल जन्माला घालण्यात अडचणी असणाऱ्या जोडप्यांसाठी राज्य-समर्थित फर्टिलिटी क्लिनिक्स अशा इतर अनेक सुविधाही मिळतील.

पैसे देणारे पहिलेच राज्य

भारतात मुलाच्या तुलनेत मुलींची संख्या कमी झाल्याने ती वाढावी, यासाठी अनेक राज्यांत योजना सुरू आहेत. यात अर्थसाहाय्याचाही समावेश आहे. मात्र त्या गर्भवती महिला किंवा स्तनदा मातांसाठी मदतीसाठी आहेत. तिसऱ्या, चौथ्या मुलाला जन्माला घालण्यासाठी पैसे देणारे आंध्र प्रदेश हे पहिलेच राज्य ठरणार आहे.

देशाच्या धोरणाला छेद

वरकरणी हे समर्थन योग्य वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात 'हम दो हमारे दो' या देशाच्या धोरणाला छेद देणारा हा निर्णय आहे. जादा मुलांचे संपोषण, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यांसाठी लागणाऱ्या सुविधा उपलब्ध आहेत का? हा खरा प्रश्न आहे.

महागाई, आरोग्य आणि शिक्षणाचा वाढता खर्च पाहता एक किंवा दोन मुलेच बस, अशी मानसिकता बहुतांशी कुटुंबांची आहे. विशेषतः साक्षर आणि नोकरीदार महिला याबाबत अधिक अग्रही दिसतात.

या धोरणात महिलांच्या मानसिकतेचा, आरोग्याचा, त्यांना होणाऱ्या त्रासाचा विचार केला जाणार आहे का?, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

लाइफ हॅक्स

प्रत्येक छोट्या पेमेंटसाठी पिन टाकून वैयागला?

आता लहान रक्कम थेट भरू शकता!

चहा, नाश्ता, पाकिंग, फोटोकॉपी, किराणा... दिवसभरात अशा अनेक छोट्या पेमेंट्स आपण यूपीआयने करतो पण प्रत्येक वेळी मोबाइल काढा, स्कॅन करा, पिन टाका... ही प्रक्रिया वारंवार करावी लागते. रक्कम फक्त १०, २० किंवा ५० रुपये असली, तरी प्रत्येक व्यवहारासाठी पिन आवश्यक असतो. यासाठीच एनसीपीआयने एक सोपी सुविधा आणली आहे. ती सुविधा म्हणजे यूपीआय लाइट. यामुळे छोट्या रकमेचे व्यवहार पिन न टाकता जलद करता येतात. त्याचबरोबर मुख्य बँक खात्याची सुरक्षितताही कायम राहते.

यामुळे काय प्रश्न सुटतो?

छोटा व्यवहारांसाठी वारंवार पिन टाकण्याची गरज राहत नाही. पेमेंट प्रक्रिया जलद होते. बँक स्टेटमेंटमध्ये छोटा व्यवहारांची गर्दी कमी होते.

काय करावयाचं?

तुमच्या यूपीआय अॅपमध्ये यूपीआय लाइट सुविधा सुरू करा आणि छोट्या व्यवहारांसाठी शिल्लक (बॅलेंस) ठेवा.

कसे कराल?



- १) तुमचं यूपीआय अॅप उघडा : फोनपे, गुगल पे, पेटीएम किंवा इतर समर्थित अॅप.
- २) यूपीआय लाइट पर्याय शोधा : मुख्य स्क्रीन किंवा प्रोफाइल विभागात हा पर्याय दिसेल.
- ३) बँक खाते निवडा : यूपीआय लाइटसाठी जोडावचं खाते निवडा.
- ४) त्यामध्ये पैसे जोडा : तुमच्या खात्यातून दराविक रक्कम यूपीआय लाइटमध्ये ट्रान्सफर करा.
- ५) व्यवहार सुरू करा : यानंतर छोट्या रकमेचे पेमेंट करताना पिन टाकण्याची गरज भासणार नाही.

महत्त्वाची सूचना

यूपीआय लाइटमध्ये ठेवलेली रक्कम मर्यादित असते. शिल्लक संपल्यास व्यवहार पूर्ण होणार नाही आणि पुन्हा रक्कम टाकावी लागेल.

अतिरिक्त फायदा

कमी वेळेत व्यवहार पूर्ण. छोट्या खर्चाचे स्वतंत्र व्यवस्थापन. मुख्य खात्यावरील ताण कमी.

लक्षात ठेवा

प्रत्येक व्यवहारासाठी पिन टाकणं सुरक्षित असलं, तरी रोजच्या छोट्या खर्चासाठी वेळखाऊ ठरू शकतं. अशा वेळी यूपीआय लाइट वेग, सोय आणि सुरक्षितता यांचा योग्य समतोल साधते.

Last Day To Join Private Channel. Closing entry for new members Now.



[Click here
to join](#)

◆ Indian Newspaper

1) Times of India

2) The Hindu

3) Business line

4) The Indian Express

5) Economic Times

And more Newspapers

◆ International Newspapers channel

[European, American, Gulf & Asia]

◆ Magazine Channel

National & International

[General & Exam related]

◆ English Editorials

[National + International Editorials]

◆ Lifetime validity at just 19 Rupees 📍

Trust me... this will be your best purchase of 2026

सीकरी के सबक याद रखिए



शशि शेखर

कभी फतेहपुर सीकरी के प्राचीर से चारों ओर नजर दौड़ा देखिए। आपको अर्द्ध रेगिस्तान की रेतीली तह में इतिहास की कराहें कसमसाती नजर आएंगी। बादशाह-ए-हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बड़ी मनखत से सन् 1571 में इसे मुगलिया सल्तनत की राजधानी घोषित किया था। इस नए-नवेले शहर का नामकरण भी उन्होंने बड़े चाव से किया था- फतेहपुर सीकरी, यानी जीत का शहर। इस नगरी को बसाने के पीछे उनका मकसद निहायत निजि, पर संवेदना से भरा हुआ था। कभी सुफ़ी संत शेख सलीम चिश्ती की रिहाइश यहां हुआ करती थी। उनके आशीर्वाद से ही अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। यहां से थोड़ी दूरी पर खनवा का वह मैदान भी मौजूद है, जहां उनके पितामह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने राणा सांगा को परास्त कर मुगल राजसत्ता की स्थापना की बुनियाद पक्का की थी।

सल्तनत की राजधानी के लिए भला इससे बेहतर और कौन सी जगह हो सकती थी? फिर गलती कहां हुई? बादशाह कुदरत की उपेक्षा कर बैठे थे। आगरा और दिल्ली की तरह यहां जलापूर्ति के लिए यमुना जैसी कोई सद्दानी नदी थी। जलापूर्ति के लिए बनाए गए जलाशयों को मौसमी वर्षा पर निर्भर रहना होता था। भूमिगत जल खारा था। नतीजतन, महज 14 साल में उन्हें राजधानी यहां से हटाकर आगरा ले जानी पड़ी। दौलताबाद को छोड़ दें, तो देश की इससे अल्पकालिक राजधानी कोई दूसरी नहीं हुई।

आपको यह एक विराट राजकीय महत्वाकांक्षा की शोकांतिका लग सकती है, पर वह 16वीं सदी थी। आज हालात उदाबने हो गए हैं। देश की कई बड़ी नदियां सूख चली हैं और उनके किनारे बसे शहर पेयजल के मामले में 'डाक जॉन' की ओर बढ़ रहे हैं। नई दिल्ली इसका अपवाद नहीं है। यह साल 'सुपर अल नोनी' का है। जो नहीं जानते, उन्हें

बता दें कि अल नोनी की स्थिति कई सालों में एक बार बनती है। ऐसा तब होता है, जब प्रशांत महासागर का तापमान दो प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ जाता है। इससे हवा में गर्मी बढ़ने लगती है और उसका रुख भी बदल जाता है। नतीजतन, दक्षिण अमेरिका में अत्यधिक बारिश और बाढ़ के हालात बन जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण एशिया में भीषण अवर्षण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी दौरान तपते हुए जंगल भी आग पकड़ते हैं, जिससे पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचती है।

भारत में सुपर अल नोनी की वजह से ही इस बार मानसून के कमजोर रहने की आशंका जताई जा रही है। मौसम शास्त्रियों का मानना है कि कुल वर्षा 90 फीसदी के आसपास होगी। यह सुकून की बात है कि अगस्त, सितंबर में राहत के हालात बन सकते हैं, लेकिन तब तक बुआई और रोपाईं में देरी हो चुकी होगी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दोहरे झटके की तरह होगा।

हम पहले ही होर्मुज जलमार्ग के बाधित होने की वजह से तरह-तरह के आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं। मैं इस विषय पर फिर कभी लंबी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारा मुद्दा जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाली दिक्कतें हैं। इस समय हम जो गर्मी महसूस कर रहे हैं, उसे भले ही सुपर अल नोनी या अन्य तात्कालिक कारणों की उपज मानी जा रही हो, लेकिन यह एक अर्द्धसत्य है। सच यह है कि अल नोनी के बिना भी हमारे शहर तपती हुई भट्टी में तब्दील होते जा रहे हैं। पिछले दिनों प्रकाशित एक रिपोर्ट से चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा हुआ था। संसार के 100 सर्वाधिक गर्म शहरों में से 97 भारत के हैं। इसके परिणाम घातक होंगे।

यह अनायास नहीं है कि देश के अधिकांश मैदानी शहरों में पारा इस समय 45 डिग्री को पार कर गया है। सरकार ने ऐसे में नागरिकों से दिन में बिना जरूरत बाहर न निकलने की अपील की है। ऐसे कितने लोग हैं, जो इस नेक सलाह का पालन करने



की कुव्वत रखते हैं?

देश का 19 फीसदी गैर-कृषि श्रमबल आज भी असंगठित क्षेत्रों में काम करता है। इसी तरह, 52 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। ये वे लोग हैं, जो रोज कुआं खोदकर पानी पीते हैं। रोजी-रोटी के लिए इन्हें घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। यह विवशता जानलेवा साबित हो सकती है। आंकड़े गवाह हैं कि पिछले पांच सालों में ताप संबंधी समस्याओं से 3,000 से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी। मध्य भारत, बुंदेलखंड, राजस्थान व अन्य मरुस्थलीय इलाके और दक्षिण भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग इस बला के चलते स्थायी या अस्थायी तौर पर पलायन कर रहे हैं।

हम कितनी फतेहपुर सीकरीयां बनाना चाहते हैं?

कई मौसम विज्ञानी मानते हैं कि यदि हालात पर काबू नहीं पाया गया, तो कुछ इलाकों में 'वेट बल्क टैपरेयर' घटने के हालात बढ़ सकते हैं। यह उमस और गर्मी का ऐसा मेल है, जिसे

सहने की क्षमता मानव शरीर में नहीं है। इसके शिकार लोग दो से छह घंटे के भीतर दम तोड़ सकते हैं। गर्मी जिस तरह साल-दर-साल बढ़ रही है, उससे यह आशंका और प्रबल हो उठी है कि आने वाले वर्षों में गंगा-यमुना के मैदानी इलाकों व तटीय क्षेत्रों से कुछ महीनों के लिए सामूहिक पलायन के हालात बन सकते हैं। यहां यह मत सोच बैठिएगा कि ऐसा जब होगा, तब देखा जाएगा। वैज्ञानिकों का एक धड़ा मानता है कि अगर उमस और गर्मी में इसी दर से बढ़ोतरी जारी रही, तो साल 2040 के आसपास यह कथामत बरपा हो सकती है।

याद रखें। मौसम कभी एकतरफा सितम नहीं ढाता। यही कारण है कि एक तरफ गर्मी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ सर्दियां रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अतिवृष्टि भी अलग से गजब ढाती रहती है। सवाल उठता है, ऐसे में किया क्या जाए? चीन और तमाम अन्य देशों के उदाहरण मौजूद हैं। उन्होंने प्राकृतिक उपायों और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों के तालमेल से इस बल को काफी काबू किया है। यहां मैं आपको अपनी परंपराओं की याद दिलाना चाहूंगा। *बृहदारण्यकोपनिषद्* की इस सुक्ति पर ध्यान दें-

मधु वाता ऋतायते मधु क्षरति सिन्धवः।

माध्वीर्न सन्तोषधीः।।

मधु नक्तमुतोषो मधुमत्वाथिर्वं रजः।

मधु धौरस्तु नः पिता।।

मधुमानो वनस्पतिर्मधुमां अस्तु सूर्यः।

माध्वीर्वावो धनन्तु नः।।

अर्थात् हमारे लिए बहने वाली हवाएं मधुर (प्राणदायी और सुखद) हैं। हमारे जलस्रोत व नदियां अमृत के समान मीठा और स्वच्छ जल प्रवाहित करें। पृथ्वी पर उगने वाली समस्त औषधियां, वनस्पतियां हमारे लिए स्वास्थ्यवर्द्धक और जीवनदायी हैं। हमारे लिए रातें शांतिपूर्ण हों और सुबह आनंद व नई ऊर्जा लेकर आएँ। इस पृथ्वी की मिट्टी उपजाऊ और कल्याणकारी हो। हमारा पालन करने वाला यह ब्रह्मांड और आकाश हमारे लिए पिता की तरह कृपालु हो। हमारे पूर्वज प्रकृति पर विजय नहीं, बल्कि इसके साथ सामंजस्य और संतुलन की साधना करते थे, ताकि उसका क्रम हमारे ऊपर अमृत बनकर बरसता रहे। हम इस महामंत्र को भूल क्यों गए हैं?

@shekharkahin @shashishekharkjournalist

जीना इसी का नाम है **देवेन्द्र कुमार** सामाजिक कार्यकर्ता

हजारों बेसहारा बहनों का वह आखिरी सहारा

दिल्ली की एक मलिन बस्ती में रह रही बूढ़ी दादी के दरवाजे पर देवेन्द्र को छोड़कर उनके माता-पिता लापता हो गए थे। दो साल के देवेन्द्र की गोद में तीन दिन की नवजात बहन! इससे बड़ी जिम्मेदारी शायद ही किसी माई को कभी मिली होगी! दादी व कुंवारी बुआ ने खून के रिश्ते की लाज बचा ली।

वो लम्हा **लांस नायक करम सिंह** परमवीर चक्र विजेता

गुस्सा वही, जो देश के काम आ जाए

ऐसा हो नहीं सकता कि कोई उन्हें छेड़कर बिना गुस्सा झेले चला गया हो। दिमाग में उबलते रहने वाला गुस्सा नाक पर धरा रहता था। मौका मिलते ही बरसने लगता था। मोहल्ले में एंग्री यंगमैन की छवि बन गई थी। जानने वाले दो हाथ दूर ही रहते थे।



तू झूठा और मैं मक्कार

इस महीने की बेस्ट सेलिंग बुक्स। इस महीने की 'टॉप टेन' पुस्तकें। हिंदी के सबसे लोकप्रिय लेखकों की बीस किताबें। हिंदी की अवश्य पढ़ने योग्य पुस्तकें। इनको नहीं पढ़ा, तो कुछ नहीं पढ़ा। हिंदी की चुनिंदा पुस्तकें। महीने की पठनीय पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं, पढ़ें, समझें व आगे बढ़ें। मेरी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकें... मेरी सबसे हिट पुस्तकें... मेरी सबसे चर्चित पुस्तकें। वाट्सएप, गूगल, एक्स आदि पर ऐसी 'बेस्ट-बेस्ट' खबरें आती हैं, तो लगता है कि हिंदी साहित्य की 'जीडीपी' टॉप पर है। ऐसी खबरें आश्चर्य करती हैं कि हजार महंगाई, बेरोजगारी हों, पुस्तकों का 'मार्केट' बन रहा है, बढ़ रहा है और वे दानादन बिक रही हैं। जिस तरह अमेरिका, यूरोप में 'बेस्ट सेलर्स' की सूची हर महीने दी जाती है, उसी तरह अपने हिंदी वाले भी करने लगें हैं। जैसे अमेरिका-यूरोप में पुस्तकें बिकती हैं, उसी तरह अपने यहां भी बिकने लगी हैं। लगता है, अब हम भी अमेरिका-यूरोप हुए जा रहे हैं और किताबी कीड़े बने जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्यकार की

लड़कों में से कई कबड्डी में इतने रम गए थे कि उन्होंने नशा करना बंद कर दिया था। जाहिर है, माता-पिता भी इस बदलाव का संज्ञान ले रहे थे। नशे की गिरफ्त से बाहर आ गए बच्चों के अभिभावक तो देवेन्द्र को अपने बेटे जैसा प्यार करने लगे थे। इस भारोसे ने देवेन्द्र के भीतर एक गहरा आत्मविश्वास भरा। इसने उनके भीतर एक सामाजिक कार्यकर्ता को जन्म दिया। उधर, घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थीं, लिहाजा वह ईडियन रेडक्रॉस से जुड़ गए। साथ ही, उन्होंने एक दवा-दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि, वहां से उन्हें नियमित पगार नहीं मिलती थी, मगर दवाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की लालच अगले दो साल तक देवेन्द्र को उस दुकान से जोड़े रखी। इन दो वर्षों में वह अच्छी तरह जान गए थे कि नेट्रोवैट-10 ओरेक्स, सिलेनी प्लस और स्पार्सोमो प्रॉक्सिसेन केमूल जैसी कई दवाइयां, जो बिना डॉक्टर की परची के नहीं बिकनी चाहिए, वे थडल्ले से बिक रही हैं। देवेन्द्र को यह भी पता लगा कि उनके नशाखोर साथी किस दवा की कितनी डोज लेते हैं?

लड़कों में से कई कबड्डी में इतने रम गए थे कि उन्होंने नशा करना बंद कर दिया था। जाहिर है, माता-पिता भी इस बदलाव का संज्ञान ले रहे थे। नशे की गिरफ्त से बाहर आ गए बच्चों के अभिभावक तो देवेन्द्र को अपने बेटे जैसा प्यार करने लगे थे। इस भारोसे ने देवेन्द्र के भीतर एक गहरा आत्मविश्वास भरा। इसने उनके भीतर एक सामाजिक कार्यकर्ता को जन्म दिया। उधर, घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थीं, लिहाजा वह ईडियन रेडक्रॉस से जुड़ गए। साथ ही, उन्होंने एक दवा-दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि, वहां से उन्हें नियमित पगार नहीं मिलती थी, मगर दवाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की लालच अगले दो साल तक देवेन्द्र को उस दुकान से जोड़े रखी। इन दो वर्षों में वह अच्छी तरह जान गए थे कि नेट्रोवैट-10 ओरेक्स, सिलेनी प्लस और स्पार्सोमो प्रॉक्सिसेन केमूल जैसी कई दवाइयां, जो बिना डॉक्टर की परची के नहीं बिकनी चाहिए, वे थडल्ले से बिक रही हैं। देवेन्द्र को यह भी पता लगा कि उनके नशाखोर साथी किस दवा की कितनी डोज लेते हैं?

जुड़ गए। साथ ही, उन्होंने एक दवा-दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि, वहां से उन्हें नियमित पगार नहीं मिलती थी, मगर दवाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की लालच अगले दो साल तक देवेन्द्र को उस दुकान से जोड़े रखी। इन दो वर्षों में वह अच्छी तरह जान गए थे कि नेट्रोवैट-10 ओरेक्स, सिलेनी प्लस और स्पार्सोमो प्रॉक्सिसेन केमूल जैसी कई दवाइयां, जो बिना डॉक्टर की परची के नहीं बिकनी चाहिए, वे थडल्ले से बिक रही हैं। देवेन्द्र को यह भी पता लगा कि उनके नशाखोर साथी किस दवा की कितनी डोज लेते हैं?



साल 2012 में पहली बार इस संस्था ने किसी से एक रुपये की मदद लिए बिना 44 लड़कियों का सामूहिक विवाह कराया। ये वह बेटियां थीं, जिनके माता-पिता की इतनी भी हैसियत न थी कि वे होने वाले दामाद की पृष्ठभूमि की छान-बीन कर पाते। यह बीड़ा भी देवेन्द्र और लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट ने उठाया।

पिता की इतनी भी हैसियत न थी कि वे होने वाले दामाद की पृष्ठभूमि की छान-बीन कर पाते। यह बीड़ा देवेन्द्र और लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट ने उठाया।

बीते 14 वर्षों में पंचश्री देवेन्द्र और उनकी संस्था ने हजारों बेवस बेटियों का विवाह कराया, हजारों को शिक्षित किया है। उनकी संस्था के प्रयासों ने देश के दस राज्यों की पच्चीस लाख गरीब लड़कियों की जिंदगी को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। अब ऐसे सफरनामों को कौन सलाम नहीं करेगा?

प्रस्तुति: चंद्रकांत सिंह

शक्ति का सदुपयोग होता है और दुरुपयोग भी। पता नहीं क्यों, शक्ति का दुरुपयोग युवाओं को ज्यादा और जल्दी आकर्षित करता है। शहर हो या गांव बड़ी संख्या में ऐसे युवा मिल जाते हैं, जो ऊर्जा और रोष से भरकर कदम उठाते हैं। वे समझ नहीं पाते हैं कि छोटी-छोटी बातों पर लड़ना-भिड़ना शक्ति का दुरुपयोग है। पंजाब के गांव सेहना में एक युवा सरदार भी शक्ति या ऊर्जा से भरे हुए थे। उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती, तो नाराजगी जताने में कभी चूकते नहीं थे। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई उन्हें छेड़कर बिना गुस्सा झेले चला गया हो। दिमाग में उबलते रहने वाला गुस्सा नाक पर धरा रहता था और मौका मिलते ही उतरने-बरसने लगता था। मोहल्ले में एंग्री यंगमैन की छवि बन गई थी। तमाम जानने वाले उनसे दो हाथ दूर ही रहते थे। एक दिन खेत से जुड़े मसले पर पड़ोसी से ही झगड़ा हो गया। पड़ोसी भी हार मानने को तैयार नहीं था, तो मामला बिगड़ गया। युवा सरदार का गुस्सा ऐसे फूटा कि लगा, हाथ उठ जाएगा, हिंसा हो जाएगी। आवाज यूं गूंजी, मानो पड़ोसी जानी दुश्मन हो। आंखें आग बरसा रही थीं। भुजाएं फड़क रही थीं, देखने से ही लग रहा था कि आज कोई अनहोनी होने वाली है। खेर, भला हो पड़ोसी का, वह पीछे हट गया, तब धीरे-धीरे मामला शांत हुआ। अपना गुस्सा समेटे सरदार जी अपने घर लौटे। मां-बाप को बड़ी चिंता थी, तो उन्होंने प्यार से समझाना शुरू किया, देखो, इतना गुस्सा ठीक नहीं। गुस्से से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। हमेशा हौश से काम लेना चाहिए। इतना गुस्सा तन-मन के लिए खराब है। देखो, कहीं जिंदगी न बिगाड़ दे। सरदार जी चुपचाप सुनते रहे। बात सही थी, उन्हें गुस्सा बहुत आता था। मां-बाप के बाद चाचा ने अलग ढंग से समझाया, गुस्सा दिखाना ही है, तो सही जगह पर दिखाओ। सिपाही बने, जंग के मैदान में गुस्से को वीरता में बदलो। अपने पड़ोसियों और गांव वालों पर ऐसे गुस्सा बरसाने से क्या फायदा? गुस्सा बरसे, तो जंग के मैदान में दुश्मनों पर बरसे, ताकि पूरा हिन्दुस्तान तुम्हारा स्वागत करे, तुम्हें हिसर-आंखों पर बिठा ले। पच्चीस वर्षीय सरदार जी के दिल में यह बात जंच गई। गांव में कुछ फौजी थे, जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़कर लौटे थे। जब वे अपनी वीर गाथा सुनाते, तो गांव वाले घेरा लगाकर सुनते और दांतों तले उंगलियां दबाते थे। सरदार जी को महसूस हो गया, बात

सही है, गुस्से की सही जगह खेत-खलिहान नहीं, जंग का मैदान है। जंग में गुस्सा खंच हो, तो देश की शान में इजाफा होता है। फिर क्या था, सरदार जी चल पड़े सुने में भर्ती होने। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, भर्ती जोरों पर थी। सेना को तो मजबूत कद-काठी के सिख जवान का इंतजार था। उन्हें बर्मा के मैदान पर जापानी सेना के खिलाफ उतार दिया गया। जंग के मोरचे में एक दिन अचानक खूंखार जापानी सैनिक सामने आ गए। मुठभेड़ हो गई, सरदार जी के पैर में गोली लगी, पर वह कहां पीछे हटने वाले थे। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। घायल होने के बावजूद साहस और निडरता से वह ऐसे लड़े कि अंग्रेज अफसरों की जुबान पर भी उनका नाम चढ़ गया- सिपाही करम सिंह। उन्हें नर्सिंग मिलिटरी मेडल से नवाजा गया, तत्काल सिपाही से लांस नायक भी बना दिया गया। खेर, यह तो महज आवाज था। देश की आजादी के तत्काल बाद जब पाकिस्तानी सेना और कबालियों ने भारत पर हमला बोला, तब लांस नायक करम सिंह अपनी चौकी के खंदक में बस तीन जवानों के साथ तैनात थे। एक घबराए जवान ने दुश्मनों की भीड़ देखकर कहा, दुश्मन बहुत हैं, हम बस चार हैं, क्या करेंगे? तब निडर लांस नायक बेधड़क खंदक से बाहर निकले और मूंछों को पेटकर बुलंद आवाज में जयकारा लगा दिया- *बोले सो निहाल, सत श्री अकाल!* जयकारा ऐसे गूंजा कि दूर-दूर तक भारतीय जवानों की रगों में वीरता का चरम उमड़ पड़ा। गौर कीजिए, इंद की वह सुबह थी। पाकिस्तानी कमांडर ने अपने जनरल को इंद के तोहफे में रिश्मार्ग गली भेंट करने का फैसला ले रखा था। एक-एक कर आठ हमले हुए और करम सिंह घायल होने के बावजूद टस से मस नहीं हुए। बार-बार कहा गया कि आप घायल हो गए हो, पीछे आ जाओ, पर लांस नायक को पीछे हटना आता ही नहीं था। वह वीर ही क्या, जो अपने देश का मोर्चा दुश्मन के लिए छोड़कर पीठ दिखा दे? रिश्मार्ग गली, तिथवाल में लांस नायक के नेतृत्व में महज 47 भारतीय वीरों ने तीन हजार से ज्यादा दुश्मनों को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। लांस नायक करम सिंह (1915-1993) इस माटी के पहले ऐसे वीर थे, जिनके चौड़े सीने पर जीते जी देश के प्रथम राष्ट्रपति ने अपने हाथों से परमवीर चक्र प्रत्याप्त था।

प्रस्तुति: ज्ञानेश उपाध्याय

तिरछी नजर

सुधीश पाचौरी हिंदी साहित्यकार

कीमत बढ़ी है। उसकी हैसियत बढ़ी है, सत्ता बढ़ी है, अर्थोपार्थि बढ़ी है। उसका भी दम है, उसके भी मानी हैं, वह किसी स्टावर से कम नहीं है। ऐसी खबरें सच हैं, तो बेस्ट सेलिंग हिंदी लेखक भी मालामाल होने चाहिए, मगर ऐसा लेखक है, पर पैसा नहीं है। लेखक बनकर नहीं जिया जा सकता, परिवार का भरण-पोषण नहीं किया जा सकता, पत्र-पत्रिका नहीं निकाली जा सकती, कैसे माना जाए कि हिंदी में कोई 'बेस्ट सेलिंग' लेखक भी है! पिछले दिनों जब एक लेखक ने बताया कि उसे एकमुश्त कोई तीस लाख रुपये की रॉयल्टी मिली, तो मन हुआ कि पूछा जाए कि सर जी,

कितना टैक्स कटा? रिटर्न भरा कि नहीं? सरकार द्वारा बनाई गई 'लखपति दीदी' हो सकती है, पर सिर्फ लेखन से बना लखपति लेखक नहीं दिखता, क्योंकि वह हो नहीं सकता; क्योंकि हिंदी की इकोनॉमी इसकी अनुमति नहीं देती। जिसके पास 'सर्प्रेस इनकम' है, वही लेखक बन सकता है। लिखने को साधन चाहिए। लेखन सर्वहारा नहीं, मध्यवर्ग का खेल है। इसका कारण है, आम हिंदी लेखक की जन्म कुंडली। हिंदी का लेखक मूलतः और अंततः एक शौकिया लेखक ही है। लेखन एक हॉबी है, खाली वक्त का काम है। मूड हुआ, तो लिखा, नहीं हुआ, तो नहीं लिखा। आईडिया आया तो लिखा, वरना नहीं। अपने मन की मांग पर लिखा, किसी और की मांग पर इनकार कर दिया।

कटाक्ष **राजेंद्र धोड़ककर**

... नहीं सर, उनका कहना है कि अबकी बार पुल टूट नहीं है, बल्कि गर्मी से पिघल कर भाप बन कर उड़ गया है।

फिल्म *तू झूठी मैं मक्कार* की तुफ़ पर ये लेखक भी कह सकते हैं- तू झूठा, मैं मक्कार!





साईस मई, 2026 को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची की पीठ ने 124 पन्नों का ऐसा फैसला सुनाया जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर बन जाएगा। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी (एसआइआर) के जरिए बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान और कई अन्य राज्यों की मतदाता सूचियों से करोड़ों नाम या तो काटे या जांच

के दायरे में रखे। एसआइआर की इस प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध करार दिया है। साथ ही एक ऐसी सीमा भी खींची है जो राजनीतिक रूप से उतनी ही महत्वपूर्ण है। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को नागरिकता की सीमित जांच का अधिकार है। हालांकि इस सीमित जांच पर असीमित सवाल भी उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विश्लेषण करता सरोकार।

नागरिकता कौन तय करेगा?

फैसले का सबसे विरोधाभासी पहलू नागरिकता की जांच ही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आयोग नागरिकता की 'सीमित जांच' कर सकता है लेकिन यह प्रथम दृष्टया और संदर्भगत आकलन है। इसे नागरिकता की घोषणा नहीं माना जाएगा। जिन व्यक्तियों के नाम साल 2003 की सूची के आधार पर काटे गए, उनके नागरिकता के प्रश्न का निर्णय सक्षम प्राधिकरण को चार हफ्ते में करना होगा—अगले लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव से पहले।

व्यावहारिक कठिनाई यह है कि सक्षम प्राधिकरण गृह मंत्रालय है। नागरिकता अधिनियम की धारा 23(4) के अनुसार किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के सीमित उद्देश्य के लिए ही आधार कार्ड के उपयोग की अनुमति है। अर्थात् एक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से काटा जा सकता है, वह नागरिकता ट्रिब्यूनल उसे भारतीय नागरिक मान सकता है, लेकिन तब तक चुनाव हो चुका होगा। यह वह संवैधानिक रिश्ता है, जिसे अभिषेक मनु सिंघवी विरोधाभास कह रहे थे।

फैसले के केंद्र में एक और सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण बात है। आयोग ने यह तय किया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया से बाहर रखे गए लोगों को केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता कि वे एक आम पुनरीक्षण के लिए अलग तरीका अपनाते हैं। पीठ ने कहा कि आयोग लोगों को मनमाने तरीके से मतदाता सूची से हटाने नहीं देगा और आयोग द्वारा काफी सुरक्षा प्रणाली अपनाई गई थी। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि जो लोग बिहार में साल 2003 की सूची से जुड़े नहीं पाए और जिनके नाम गलती से काटे गए (अनुपस्थित, मृत, स्थानांतरित या दुर्घटित के आधार पर) वे न्यायिक समीक्षा के माध्यम से कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भी जा सकते हैं।

दूसरा- नागरिकता ट्रिब्यूनल की व्यवस्था मजबूत होगी। जिन लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं, उन्हें अब नागरिकता की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तीसरा- शुभेदु अधिकारी का बयान यह संकेत देता है कि एसआइआर और कल्याण योजनाओं की पात्रता सूची को आपस में जोड़ा जाएगा। अगर बंगाल में लक्ष्मी भंडार की 30 लाख लाभाधिकियों को अपात्र ठहराया जाएगा क्योंकि उनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, तो यह एक नई राजनीतिक-प्रशासनिक जटिलता पैदा करेगा। चौथा- इस फैसले के बाद विपक्ष के पास जो एकमात्र रास्ता है, वह है, नागरिकता ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक और त्वरित बनाने की मांग करना। योगेंद्र यादव ने इस फैसले की तुलना एडीएम जबलपुर मामले से की। साल 1976 में एडीएम जबलपुर में सर्वोच्च न्यायालय ने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन को वैध ठहराया था, जिसे बाद में भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी भूलों में से एक माना गया। यादव की तुलना विवादस्पद है, लेकिन यह एक संकेत है कि

मताधिकार और नागरिकता के प्रश्न का संघर्ष अदालत से निकलकर अब राजनीतिक और सामाजिक मंच पर आ गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने नाम काटे जाने वाले लोगों के लिए एक महत्पूर्ण राहत भी दी है। न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि सक्षम प्राधिकरण (गृह मंत्रालय) किसी को भारतीय नागरिक घोषित करता है, तो उसका नाम मतदाता सूची में वापस जोड़ा जाएगा। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि जो लोग बिहार में साल 2003 की सूची से जुड़े नहीं पाए और जिनके नाम गलती से काटे गए (अनुपस्थित, मृत, स्थानांतरित या दुर्घटित के आधार पर) वे न्यायिक समीक्षा के माध्यम से कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भी जा सकते हैं।

इस फैसले के दूरगामी निहितार्थ हैं?

पहला- निर्वाचन आयोग अब पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण का विस्तार कर सकता है। भविष्य में जहाँ भी विधानसभा चुनाव होंगे, वहाँ एसआइआर पहले से हो सकता है।

कानूनी पहलू सही, जमीनी हकीकत को गलत समझा

इस पूरी बहस में सबसे संतुलित और अधिकारपूर्ण आवाज आई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी की। उन्होंने एक लेख लिखकर फैसले के दोनों पहलुओं को तटस्थ दृष्टि से परखा। कुरैशी ने लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी पहलू सही समझा, लेकिन जमीनी हकीकत गलत समझी।

पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल- जो हुआ, वह वास्तव में एसआइआर था ही नहीं। यह डे-नोवो यानी शून्य से नई सूची तैयार करने की कवायद थी। साल 2003 की पुरानी सूची को रद्द करके नई सूची बनाई गई। तीन दशकों में आयोग ने वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षणों के जरिए मतदाता सूची में करीब 99 फीसद संशोधन हासिल की थी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव उन्हीं सूचियों पर बिना किसी विवाद के हुए। उस विश्वसनीय काम को रद्द की टोकरी में डालकर एक अरब मतदाताओं को फिर से सत्यापन के लिए बाध्य करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21(3) के अर्थ में एसआइआर नहीं है।

दूसरा बड़ा सवाल- गलत बहिष्करण का उपाय। न्यायालय ने कहा कि गलती से नाम काटे गए लोग न्यायिक समीक्षा का रास्ता अपना सकते हैं। कुरैशी ने इस पर तीखा प्रश्न उठाया : क्या न्यायालय को यह उपाय देना है? वह सीतामढ़ी या मुर्शिदाबाद का दैनिक मजदूर है, जो शायद अपना नाम मसविदा सूची में देखने भी नहीं गया। जिसके पास वकील नहीं, पैसा नहीं, और सक्षम प्राधिकरण के सामने याचिका दायर करने की कानूनी साक्षरता भी नहीं। न्यायिक समीक्षा उनके लिए है, जिनके पास समय और संसाधन हों। गरीब मतदाता के लिए यह दरवाजा बंद

करने का तरीका है, खोलने का नहीं। मतदाता सूची कोई नौकरशाही दस्तावेज नहीं है। यह व्यवहार में हर नागरिक का लोकतांत्रिक अपनेपन का प्रमाणपत्र है। हर गलत तरीके से हटायी गयी नाम लोकतंत्र से इनकार है। राज्य के किसी दुश्मन द्वारा नहीं, बल्कि राज्य द्वारा खुद। तीसरा सवाल- नागरिकता रिकॉर्ड की अस्थिरता। न्यायालय ने कहा कि सक्षम प्राधिकरण चार सप्ताह में नागरिकता का निर्णय करे। लेकिन नागरिकता अधिनियम के तहत करोड़ों मामलों को संभालने का कोई ढांचा ही नहीं है। गैर-अनुपालन पर कोई दंड भी नहीं। यानी यह निर्देश व्यावहारिक रूप से खोखला है और यदि प्राधिकरण समय पर निर्णय नहीं कर पाता, तो वह व्यक्ति न मतदाता रहेगा, न नागरिकता सिद्ध कर पाएगा और चुनाव हो चुका होगा। चौथा सवाल- मतदाता पहचान पत्र का खाल्टा। एकमात्र विश्वसनीय पहचान पत्र को एक झटके में खत्म कर दिया गया। भारत के एक बड़े वर्ग, विशेषकर गरीब के पास यही एकमात्र सरकारी पहचान पत्र था। अब उन्हें बारह में से कोई एक दस्तावेज (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र) को एक झटके में खत्म कर दिया गया। भारत के एक बड़े वर्ग, विशेषकर गरीब के पास यही एकमात्र सरकारी पहचान पत्र था। अब उन्हें बारह में से कोई एक दस्तावेज लाना है, जो उनके पास है ही नहीं। यह व्यवस्था उन्हीं को दंडित करती है, जिन तक लोकतंत्र की पहुंच का विस्तार करने के लिए तीन दशकों में काम हुआ था।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की इस आलोचना का महत्त्व इसलिए अधिक है क्योंकि वे न तो विपक्षी राजनेता हैं, न आंदोलनकारी। वे उसी संस्था के पूर्व प्रमुख हैं, जिसने एसआइआर किया। उनका यह कहना कि न्यायालय ने अनजाने में वकीलों पर करोड़ों गलत तरीके से हटाए गए मतदाताओं की याचिकाओं का बोझ डाल दिया है, एक संस्थागत अनुभव है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

एसआइआर की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने माना वैध संसद से लेकर सड़क तक चल रहा था संघर्ष

सुप्रीम आयोग!

जनसत्ता सरोकार

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर यह फैसला किसी एक कानूनी प्रश्न का उत्तर नहीं है। वास्तव में यह उस व्यापक संघर्ष की परिणति है जो एक वर्ष से अधिक समय से देश की अदालतों, संसद की सीटियों और सड़कों पर लड़ी गई। एक तरफ भाजपा जो पुनरीक्षण को मतदाता सूची की सफाई और चुसपैठियों को बाहर करने का अभियान बताती रही, वहीं विपक्ष, नागरिक समाज और नागरिक संस्थाएं इसे मताधिकार के हनन का षड्यंत्र कह रहे थे। उच्चतम न्यायालय ने दोनों को आंशिक रूप से सुना और आंशिक रूप से निराश किया।

बिहार से शुरुआत

जून 2025 में निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की। 24 जून से 25 जुलाई के बीच बिहार के 7.89 करोड़ मतदाताओं के विवरण की जांच की गई। एक अगस्त को प्रारूप सूची जारी हुई, जिसमें 65.62 लाख नाम हटाए गए थे। अनुपस्थित, मृत, स्थानांतरित या दोहरे के आधार पर। विपक्ष ने इसकी मुखाफलत की। राजद के मनोज झा, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, तृणमूल की महुआ मोईत्रा, राकांपा (शरद पवार) की सुप्रिया सुले और योगेंद्र यादव सहित कई याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

आयोग की दलील थी कि साल 1962 के बाद पहली बार मतदाता सूची की ऐसी गहन समीक्षा की जा रही है। 20 वर्षों में तेज शहरीकरण और पलायन के कारण सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि यह एनआरसी जैसी प्रक्रिया है, जिसमें नागरिकता की परीक्षा जांच हो रही है, जो आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। प्रश्नों भूषण ने तर्क दिया कि प्रक्रिया गैर पारदर्शी है और 10 फीसद से अधिक मतदाताओं को हटाया गया।

बंगाल : 91 लाख नाम हटे, 25 लाख अपीलें

बिहार के बाद पुनरीक्षण का केंद्र बना पश्चिम बंगाल। वहाँ साल 2026 के विधानसभा चुनाव होने थे। 16 दिसंबर 2025 को निर्वाचन आयोग ने बंगाल की प्रारूप मतदाता सूची जारी की। 7.66 करोड़ पूर्व मतदाताओं में से 58.21 लाख नाम हटा दिए गए। 124.16 लाख मृत, 32.65 लाख स्थानांतरित/अनुपस्थित और 1.38 लाख दोहरे। इसके अलावा 31.38 लाख 'अनमैड' मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया गया जो साल 2002 की सूची से नहीं जुड़े थे।

तृणमूल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया था। ममता बनर्जी ने खुद निर्वाचन आयोग से मिलकर विरोध जताया। तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि 58 लाख नाम बिना नोटिस या व्यक्तिगत सुनवाई के काटे गए। सुनवाई के बाद अंततः बंगाल में कुल 91 लाख नाम हटाए गए। एक रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में गहन पुनरीक्षण से जुड़े अपीलीय न्यायाधिकरणों में कुल 25 लाख से अधिक अपीलें दाखिल की गईं। लेकिन मई 2026 तक केवल 6,581 मामलों का निपटारा हो पाया। यानी कुल अपीलों का महज 0.26 फीसद। सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2026 में 19 अपीलीय न्यायाधिकरण बनाए थे, जिनमें उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नियुक्त किए गए।

फैसले के मुख्य बिंदु : क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने 124 पन्नों के फैसले में तीन केन्द्रीय प्रश्नों का उत्तर दिया। पहला- क्या आयोग को एसआइआर का अधिकार है? दूसरा- क्या प्रक्रिया वैध उद्देश्य पर आधारित थी? तीसरा- क्या इसमें कानून का उल्लंघन हुआ? तीनों के उत्तर में न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के पक्ष में फैसला दिया।

कल्याणकारी योजनाओं पर भी असर

सले के दिन ही 27 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा बयान दिया जो पुनरीक्षण और कल्याणकारी योजनाओं को एक साथ में पिरो देता है। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना की 2.20 करोड़ लाभाधिकियों में से करीब 30 लाख महिलाएं अपात्र हैं। मुख्यमंत्री अधिकारी के अनुसार ये 30 लाख महिलाएं या तो मृत हैं, काल्पनिक हैं, या ऐसी हैं जिनके नाम मतदाता सूची से स्थायी रूप से हटाए जा चुके हैं। इनमें वे भी शामिल हैं जो पुनरीक्षण से जुड़े ट्रिब्यूनल में नहीं पहुंचे या जिन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया। यह बयान सीधे तौर पर एसआइआर को अपात्र-कल्याण सफाई से जोड़ता है, जो

न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत आयोग को विशेष गहन पुनरीक्षण का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है। यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को संवैधानिक अनिवार्यता को आगे बढ़ाती है। पीठ ने स्पष्ट किया कि एसआइआर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 या निर्वाचक रजिस्ट्रेशन नियम 1960 के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 324 को धारा 21 (3) के माध्यम से जीवित करता है। सबसे महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से संवेदनशील बिंदु था- नागरिकता। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि आयोग नागरिकता की सीमित जांच कर सकता है, लेकिन उसका निर्णय नागरिकता पर अंतिम नहीं

मतदाता सूचियों के आधार पर 10 फीसद से अधिक मतदाताओं को एक गैर-पारदर्शी प्रक्रिया में हटाया गया।

योगेंद्र यादव ने इस फैसले को आपातकाल युग के 'एडीएम जबलपुर' फैसले से तुलना करते हुए इसे संवैधानिक पराजय कहा। उन्होंने लिखा कि यह भारतीय लोकतंत्र की अंतिम संवैधानिक दीवार के ढहने का प्रतीक है। यादव ने यह भी कहा कि वे फैसला सुनने अदालत नहीं गए क्योंकि उनके अनुसार यह मामला बहुत पहले ही तय हो चुका था।

कांग्रेस के कानूनी मामलों के विभाग के अध्यक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि फैसले में जितने जवाब दिए गए हैं, उससे अधिक सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने फैसले में विरोधाभासों की ओर ध्यान दिलाया, जैसे कि आयोग को नागरिकता की सीमित जांच का अधिकार देना, लेकिन अंतिम निर्णय से वंचित रखना। यह स्थिति व्यावहारिक रूप से कठिन है क्योंकि अगर आयोग नाम काट देता है और बाद में वह व्यक्ति नागरिक पाया जाता है, तो चुनाव हो चुका होगा।

भाजपा की प्रतिक्रिया : विपक्ष का झम झम

भाजपा ने फैसले का स्वागत किया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुप ने कहा कि यह फैसला निर्वाचन आयोग की संवैधानिक शक्तियों और लोकतंत्र की पारदर्शिता को मजबूत करता है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह वोट बैंक की राजनीति के लिए एसआइआर का विरोध कर रहा था। भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने एसआइआर का विरोध इसलिए किया क्योंकि वे अवैध चुसपैठियों के साथ खड़े थे, भारतीय मतदाताओं के साथ नहीं। भाजपा ने

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

पुनरीक्षण वैध है

बिहार में पुनरीक्षण के दौरान सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी

पश्चिम बंगाल में नाम काटे जाने पर गहरा विवाद हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में गहरा विवाद के कारण ट्रिब्यूनल बनाए।

ट्रिब्यूनल में जितनी सुनवाई हुई चुनाव से पहले, उस हिसाब से अधिकतर मतदाता योग्य पाए गए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता तय करने का अंतिम अधिकार गृह मंत्रालय के पास है

चुनाव आयोग को प्रक्रिया के दौरान नागरिकता की सीमित जांच का अधिकार

बिहार से लेकर बंगाल तक काफी मतदाताओं के नाम काटे गए हैं

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्या बागची की पीठ ने यह फैसला दिया

होगा। यह निर्णय सक्षम प्राधिकरण, मुख्यतः गृह मंत्रालय को करना होगा। न्यायालय ने कहा, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं। न्यायालय ने कहा कि आधार कार्ड को मतदान पात्रता के प्राथमिक दस्तावेज के रूप में नहीं माना जा सकता, हालांकि बिहार की संशोधित सूची में पहचान सत्यापन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में इसे मान्यता दी गई थी।

फैसला आते ही तीखी प्रतिक्रिया भी आई

प्रशांत भूषण ने इसे न्यायपालिका का काला दिन बताते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक पक्षपाती चुनाव आयोग को कोरा चेक दे दिया। उनका तर्क था कि कई राज्यों में चुनाव पहले ही हो चुके हैं। संशोधित

विपक्ष के उस आरोप की पुष्टि करता है कि एसआइआर का उद्देश्य केवल मतदाता सूची नहीं, बल्कि कल्याण योजनाओं की पात्रता का पुनर्निर्धारण भी था।

महाराष्ट्र में भाजपा नीत सरकार ने भी लाडकी बहिन योजना के लेखे में 69 लाख नाम हटाए थे जो ई-केवाईसी और दस्तावेज सत्यापन में विफल रहे। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार की नई अन्नपूर्णा भंडार योजना, जिसके तहत 3,000 रुपए मासिक मिलेंगे, के लिए एक नई पारदर्शी सूची बनाई जाएगी। लाभाधिकियों के पास नए फार्म भरने के लिए 90 दिन का समय है।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हमें लग रहा था कि लक्ष्मी भंडार की लाभाधी सूची सत्यापित है। लेकिन हमें ऐसी शिकायतें मिलीं कि लगभग 30 लाख लोग, जिनके नाम मतदाता सूची से स्थायी रूप से हटाए गए हैं, वे अभी भी पैसे ले रहे हैं।

आयोग की दलील थी कि साल 1962 के बाद पहली बार मतदाता सूची की ऐसी गहन समीक्षा की जा रही है। 20 वर्षों में तेज शहरीकरण और पलायन के कारण सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो गई थीं। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि यह एनआरसी जैसी प्रक्रिया है, जिसमें नागरिकता की परीक्षा जांच हो रही है, जो आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। एडीआर का सवाल था कि 90 फीसद नाम गलत क्यों काटे गए?

एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिकॉर्स (एडीआर) इस पूरे मामले का मूल याचिकाकर्ता थी। एडीआर ने एसआइआर की प्रक्रिया, समयसीमा और पारदर्शिता पर तीन मुख्य आपत्तियां उठाई थीं।

पहली- आयोग ने मतदान से महज कुछ महीने पहले बड़े पैमाने पर नाम काटने की कवायद की, जिससे लाखों वैध मतदाता वंचित हो सकते हैं।

दूसरी- नागरिकता जांच आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है। 65 लाख बिहार और 91 लाख बंगाल के मतदाताओं के आंकड़े सत्यापन की प्रक्रिया की खा미यां उजागर करते हैं।

तीसरी-सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह था जो याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के समक्ष रखा- सुनवाई के दौरान जिन मामलों का निपटारा हुआ उनमें से लगभग 90 फीसद में पाया गया कि नाम गलत काटे गए। अर्थात् जो मतदाता सुनवाई में पहुंचे और दस्तावेज प्रस्तुत किए, उनमें से नौ में से नौ वैध नागरिक निकले। यह आंकड़ा दर्शाता है कि प्राथमिक सफाई कितनी अपरिपक्व थी। हालांकि बंगाल में ट्रिब्यूनल ने मात्र 6,581 मामलों का ही निपटारा किया और 25 लाख अपीलें लंबित रहीं।

सवाल सामाजिक अधिकारों का

एसआइआर पर सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला एक विरोधाभासी दस्तावेज है। एक तरफ यह निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संवैधानिक मान्यता देता है, दूसरी तरफ नागरिकता के प्रश्न को अनिर्धारित छोड़ देता है। इससे एक नई प्रशासनिक-न्यायिक भ्रंशला बनती है, जिसमें मतदाता सूची से कटे लाखों लोगों को गृह मंत्रालय और ट्रिब्यूनल के चक्कर लगाने पड़ेंगे।

पश्चिम बंगाल में 25 लाख लंबित अपीलों, 90 फीसद मामलों में गलत कटौती का तथ्य और ट्रिब्यूनलों द्वारा मात्र 0.26 फीसद मामलों का निपटारा, ये आंकड़े बताते हैं कि प्रक्रिया की वैधानिकता और उसके क्रियान्वयन के बीच की खाई अभी भी नहीं है। जब शुभेंदु अधिकारी एसआइआर और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को एक साथ जोड़ते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि मतदाता सूची की सफाई केवल चुनावी प्रक्रिया का प्रश्न नहीं, सामाजिक अधिकारों का प्रश्न भी है।

भारतीय लोकतंत्र में मतदाता सूची कभी महज प्रशासनिक दस्तावेज नहीं रही। यह नागरिकता की सामाजिक पहचान है। जो सूची में है, वह भारतीय है। जो नहीं है, उसे साबित करना होगा कि वह कौन है। सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मई को यह सवाल तय नहीं किया। उसने केवल यह तय किया कि यह सवाल पूछने का अधिकार किसके पास है।

-प्रस्तुति : संजय शर्मा

एकजुट हुए काकरोच

काकरोच कोई बुरा या अपमानजनक शब्द नहीं है। *विकीपीडिया* पर खोज करने से पता चलता है कि काकरोच ने लगभग 20 करोड़ वर्षों से अपनी मूल शारीरिक संरचना को बरकरार रखा है- यानी इंसानों (*होमो सैपियंस*) के अफ्रीका में लगभग तीन लाख वर्ष पहले पैदा होने से 19 करोड़ 97 लाख वर्ष पहले से। इस दुनिया में रहने का अधिकार इंसानों से पहले काकरोच का बनता है।

विज्ञान विश्वकोश बताता है कि काकरोच लोगों को काटते या उन पर हमला नहीं करते, जबकि लोग उन पर हमला करते हैं। बेशक, काकरोच जीवाणु के वाहक होते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं और एलर्जी पैदा करते हैं। मनुष्य भी जीवाणु का वाहक होता है, बीमारियाँ फैलाता है और एलर्जी पैदा करता है (विशेषकर प्रतिद्वंद्वी समूहों के सदस्यों के बीच)। कुछ मनुष्य काकरोच को 'घिनौना' मानते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कुछ लोग दूसरे लोगों को 'घिनौना' मानते हैं।

हलचल और खलबली

कुछ दिन पहले, एक उच्च पद पर आसीन सम्माननीय ने काकरोच को उनकी नींद से जगा दिया। ईश्वर उनका भला करे, उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया कि उनका तात्पर्य अदालतों में घूम रहे नकली डिग्रियों वाले फर्जी वकीलों से था। ऐसे फर्जी वकीलों को बुरा-भला कहा जा सकता है, लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि उन्हें काकरोच कहना उचित नहीं। एक बार हलचल मचने पर काकरोच हरकत में ही रहते हैं (जैसे 'एक बार गिरवी, हमेशा गिरवी')। हरकत में आए कुछ काकरोच ने एक राजनीतिक दल बना लिया है, 'एक्स' पर एक खाता बनाया है, एक वेबसाइट शुरू की है और इंटरग्राम पर भी खाता बनाया है। नवीनतम गणना के अनुसार, उस खाते के 2.2 करोड़ से अधिक फालोअर थे। हरकत में आए काकरोचों ने पलटवार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि इंसानों में भी *हलचल हुई और खलबली मच गई*। मुझे संदेह

है कि इंसान अपनी कोल्हापुरी चप्पलों में कांप रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है, तो देश की सर्वोच्च कार्यकारी संस्था, जिसके सशस्त्र बलों में 14 लाख सक्रिय सैनिक, 4200 मुख्य युद्धक टैंक, 580 लड़ाकू विमान, 270 नौसैनिक पोत, दो विमानवाहक पोत और सैकड़ों परमाणु हथियार हैं, और आरबीआइ से प्राप्त 2,86,588 करोड़ रुपए का अनुदान है, वह केवल डिजिटल मंच पर बनी काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के ध्वजवाहक तीस वर्षीय अभिजीत दिपके द्वारा एक्स पर बनाए गए एक साधारण खाते से क्यों डरेंगी और एक्स को यह खाता बंद करने के लिए क्यों कहेंगी?

दिपके एक दूर देश में हमारे मित्र-शत्रु डोनाल्ड ट्रंप की देखरेख में 'जनसंपर्क' (खतरनाक एआई नहीं) विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। वेबसाइट पर सीजेपी के लक्ष्य बताए गए हैं: हम काकरोच की पहचान को स्वीकार करते हैं- 'अगर युवाओं की बात सुने जाने के लिए यह जरूरी है, तो यही सही।' 'आलसी और बेरोजगारों की आवाज' के नारे के साथ सीजेपी उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, जिन्हें 'व्यवस्था गिनना भूल गई'। वे बेरोजगार, आलसी, हमेशा आनलाइन रहने वाले और पेशेवर तरीके से शिकायत करने वाले लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। वे महात्मा गांधी, भीमराव आंबेडकर और जवाहर लाल नेहरू से प्रेरित हैं। सीजेपी का घोषणापत्र हस्ताला भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है, जबकि आम राजनीतिक दलों के घोषणापत्र इतने नीरस होते हैं कि नींद आने लगती है।



दूसरी नजर

पी चिदंबरम

'आलसी और बेरोजगारों की आवाज' के नारे के साथ सीजेपी उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, जिन्हें जिन्हें 'व्यवस्था गिनना भूल गई'। वह बेरोजगार, आलसी, हमेशा आनलाइन रहने वाले और पेशेवर तरीके से शिकायत करने वाले लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। वह महात्मा गांधी, भीमराव आंबेडकर और जवाहर लाल नेहरू से प्रेरित हैं।

'यही कारण है'

मुझे लगता है कि सीजेपी जनता, विशेषकर युवा वर्ग के बीच व्याप्त निराशा, बेचैनी और हताशा पर भरोसा कर रही है। इसके कारण हैं: **बेरोजगारी:** बेरोजगारी दर 5.2 फीसद है, युवा बेरोजगारी दर 16-17 फीसद है। कार्यबल 64.3 करोड़ है और श्रम बल सहभागिता दर अधिकतम 60 फीसद है। शेष 40 फीसद या लगभग 25 करोड़ लोग- क्षमा करें- काकरोच हैं। यदि सीजेपी को इन सभी काकरोच के वोट मिल जाएं, तो वह सरकार बना लेगी। (2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को 23.6 करोड़ वोट और कांग्रेस को 13.7 करोड़ वोट मिले थे)।

पेट्रोल और डीजल: गतिशीलता काकरोच के लिए जीवन का आधार है। ईंधन की ऊंची कीमतें उनकी गतिशीलता को सीमित कर रही हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए और डीजल की 95.20 रुपए है। भाजपा को वोट देने के बदले कोलकाता के निवासियों को क्रमशः 113.51 रुपए और 99.82 रुपए की कीमत चुकानी पड़ रही है। **कारखानों में नौकरियां:** काकरोच स्वभाव से आलसी होते हैं। चूँकि वे हर सुबह जल्दी उठकर मोहल्ले की शाखा में नहीं जाते, इसलिए उन्हें सरकार की ओर से कभी रोजगार नहीं मिलेगा। उनके लिए दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है कारखाने की नौकरी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, देश में 2,60,061 पंजीकृत कारखाने हैं। इन कारखानों में नौकरियों की अनुमानित संख्या

सवालियों का पिटारा

जिम्हना क्लब को बंद करने की कोशिश ने एक ऐसा पिटारा खोल दिया है जिसमें से निकल रहे हैं कई अहम सवाल। जिनको अभी तक इस विवाद के बारे में पूरी जानकारी नहीं है उनके लिए संक्षेप में पहले बता दूँ कि मुद्दा क्या है। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बन कर लुटियंस दिल्ली में रहने लगे हैं, उन्होंने दिल लगा कर कोशिश की इस संप्रदाय रिहाइशी इलाके की शकल बदलने की। इस प्रयास में उन्होंने नया संसद भवन बनाया है रायसीना पहाड़ी पर, और जो सरकारी दफ्तर बने थे अंग्रेजों के जमाने में उनकी खाली कर नए आधुनिक भवनों में भेज दिया है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की ओर जो सड़क जाती है उसका नाम राजपथ से बदल कर कर्तव्यपथ रखा है और अपने नए कार्यालय को 'सेवा तीर्थ' का नाम दिया है।

कुछ वर्ष पहले जब जिमखाना क्लब की कार्यसमिति में उन्होंने कुछ सरकारी अफसर नियुक्त किए थे, तो ऐसा लगा था इस क्लब के सदस्यों को कि यह पहला कदम है उस सरकारी जमीन को वापस लेने के लिए जिस पर यह क्लब बना था 113 साल पहले। ऐसा ही हुआ पिछले सप्ताह, जब क्लब को सूचना भेजी गई कि जून के पहले सप्ताह तक क्लब सरकार को जमीन वापस करे जिसके लिए सालाना सिर्फ हजार रुपए का किराया सरकार को मिलता रहा है। क्लब ने इस सूचना को अदालत में चुनौती दी है और ऐसा हो सकता है कि उसको थोड़ी बहुत मोहलत मिल जाए, लेकिन दिल्ली में अफवाहें अब यह भी उड़ रही हैं कि सरकार का इरादा है प्रधानमंत्री आवास के पास रेसकोर्स और पोला ग्राउंड की जमीन भी वापस लेने का। यहां याद दिलाना चाहती हूँ कि लुटियंस दिल्ली की सारी जमीन सरकारी है जो लोगों को सी साल या 99 साल की लीज पर दी गई है।

तो अगर इस एक क्लब की जमीन सरकार वापस लेने को तैयार है इस आधार पर कि सार्वजनिक जमीन का निजी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं पूछते हैं हम कि इस आधार पर सरकारी अशोक होटल और सम्राट होटल भी बंद किए जाएं? ये भी तो प्रधानमंत्री के आवास के कुछ ज्यादा नजदीक हैं और उनकी

कुंजी छतों से कोई प्रधानमंत्री के आवास पर हमला करना चाहे, तो जिमखाना क्लब से कहीं ज्यादा आसान है। प्रधानमंत्री आवास के पीछे कई कोठियां हैं जिनमें मंत्री और सांसद रहते हैं और जिमखाना क्लब के सामने है इंदिरा गांधी का पुराना घर जो उनके बेटे ने स्मारक बना दिया था और खुद उस घर में रहने लगे, जो आज प्रधानमंत्री आवास कहलाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री रहा करते थे तीनमूर्ति भवन में जिसको उनकी बेटों ने स्मारक बना दिया था

पर कोठियां बना कर बसाया जाए? रही बात सांसदों की, तो उनके लिए कई सरकारी होटल हैं संसद के आसपास जिनमें इतने कम ग्राहक आते हैं कि आधे खाली रहते हैं साल भर। इनमें सांसदों के लिए जगह बन सकती है उन महीनों के लिए जब संसद का सत्र चल रहा होता है। उनको क्यों बड़ी-बड़ी कोठियों की जरूरत है? अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास स्थायी और सुरक्षित होना चाहिए। न कि ऐसा घर जिसको जब किसी के मन में आए स्मारक बना दिया जाए। विनम्रता से प्रधानमंत्री को सुझाव देना चाहती हूँ कि जब तक उनकी नई कोठी तैयार नहीं होती है इंडिया गेट के पास, वे क्यों नहीं तीनमूर्ति भवन में रहना शुरू करें नेहरू स्मारक को कहीं और बनवा कर। तीनमूर्ति भवन शानदार भी है और सुरक्षित भी।

युद्ध के इस दौर में जब प्रधानमंत्री ने गरीबों को खर्चा कम करने के लिए कहा है, तो क्यों नहीं अपनी सरकार को ऐसा करने का आदेश देते हैं? जितनी फिजूलखर्ची हम करते हैं मंत्रियों के कार्यालयों और कोठियों पर, इसको बंद करना क्या 'देशभक्ति' नहीं होगी मुसीबत के इस दौर में? लुटियंस दिल्ली की जमीन भारत में सबसे महंगी मानी जाती है, तो क्यों नहीं इसका व्यावसायिक इस्तेमाल हो?

अपने पिता की याद में। सच तो यह है कि इस पहले घर को स्मारक न बनाया होता, तो प्रधानमंत्री का स्थायी और सुरक्षित आवास आज भी होता। स्मारक और समाधियां इतनी हैं दिल्ली में कि कई लोग दिल्ली को मुर्दों का शहर कहते हैं मजाक में, लेकिन जिस तरह सरकारी जमीन का फिजूल इस्तेमाल हो रहा है देश की राजधानी में, वह मजाक नहीं गंभीर मसला है। मंत्रियों और सांसदों को हमने बताया है ऐसी कोठियों में जिनकी कीमत बाजार में कम से कम पांच सौ करोड़ रुपए है। ऊपर से यह भी ध्यान में रखिए कि राष्ट्रपति भवन के बाग-बागीचे 300 एकड़ जमीन पर हैं? क्या राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 300 एकड़ जरूरी हैं?

सवाल और भी निकल रहे हैं उस पिटारे से। मंत्रियों को अगर इस देश की गरीब जनता के पैसों से बसाना ठीक समझाती है भारत सरकार, तो क्यों नहीं इनको राष्ट्रपति भवन की 300 एकड़ जमीन

दौर में? लुटियंस दिल्ली की जमीन भारत में सबसे महंगी मानी जाती है, तो क्यों नहीं इसका व्यावसायिक इस्तेमाल हो? इस तरह की शुरुआत अगर दिल्ली में होगी, तो राज्यों में भी होने लगेंगी और खूब पैसा बचंगा देश का। फिलहाल प्रधानमंत्री के कहने पर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं उनके मुख्यमंत्री और मंत्री। कभी किसी मुख्यमंत्री की पत्नी साइकिल पर सवार होकर निकलती है टीवी पत्रकारों के सामने, तो कभी कोई मुख्यमंत्री स्कूटर पर सवार होकर निकलते हैं पत्रकारों को दिखाने के लिए। जब आर्थिक संकट पूरे देश में आया है, तो इस तरह के तमाशे बंद होने चाहिए और सरकारी अफसरों और राजनेतों को दिल लगा कर देश का पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। यही होगी असली देशभक्ति। कहा था न मैंने कि जिमखाना क्लब बंद होने से खुल गया है सवालियों का बहुत बड़ा पिटारा।

युद्ध के इस दौर में जब प्रधानमंत्री ने गरीबों को खर्चा कम करने के लिए कहा है, तो क्यों नहीं अपनी सरकार को ऐसा करने का आदेश देते हैं? जितनी फिजूलखर्ची हम करते हैं मंत्रियों के कार्यालयों और कोठियों पर, इसको बंद करना क्या 'देशभक्ति' नहीं होगी मुसीबत के इस दौर में? लुटियंस दिल्ली की जमीन भारत में सबसे महंगी मानी जाती है, तो क्यों नहीं इसका व्यावसायिक इस्तेमाल हो? इस तरह की शुरुआत अगर दिल्ली में होगी, तो राज्यों में भी होने लगेंगी और खूब पैसा बचंगा देश का। फिलहाल प्रधानमंत्री के कहने पर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं उनके मुख्यमंत्री और मंत्री। कभी किसी मुख्यमंत्री की पत्नी साइकिल पर सवार होकर निकलती है टीवी पत्रकारों के सामने, तो कभी कोई मुख्यमंत्री स्कूटर पर सवार होकर निकलते हैं पत्रकारों को दिखाने के लिए। जब आर्थिक संकट पूरे देश में आया है, तो इस तरह के तमाशे बंद होने चाहिए और सरकारी अफसरों और राजनेतों को दिल लगा कर देश का पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। यही होगी असली देशभक्ति। कहा था न मैंने कि जिमखाना क्लब बंद होने से खुल गया है सवालियों का बहुत बड़ा पिटारा।

युद्ध के इस दौर में जब प्रधानमंत्री ने गरीबों को खर्चा कम करने के लिए कहा है, तो क्यों नहीं अपनी सरकार को ऐसा करने का आदेश देते हैं? जितनी फिजूलखर्ची हम करते हैं मंत्रियों के कार्यालयों और कोठियों पर, इसको बंद करना क्या 'देशभक्ति' नहीं होगी मुसीबत के इस दौर में? लुटियंस दिल्ली की जमीन भारत में सबसे महंगी मानी जाती है, तो क्यों नहीं इसका व्यावसायिक इस्तेमाल हो? इस तरह की शुरुआत अगर दिल्ली में होगी, तो राज्यों में भी होने लगेंगी और खूब पैसा बचंगा देश का। फिलहाल प्रधानमंत्री के कहने पर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं उनके मुख्यमंत्री और मंत्री। कभी किसी मुख्यमंत्री की पत्नी साइकिल पर सवार होकर निकलती है टीवी पत्रकारों के सामने, तो कभी कोई मुख्यमंत्री स्कूटर पर सवार होकर निकलते हैं पत्रकारों को दिखाने के लिए। जब आर्थिक संकट पूरे देश में आया है, तो इस तरह के तमाशे बंद होने चाहिए और सरकारी अफसरों और राजनेतों को दिल लगा कर देश का पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। यही होगी असली देशभक्ति। कहा था न मैंने कि जिमखाना क्लब बंद होने से खुल गया है सवालियों का बहुत बड़ा पिटारा।

युद्ध के इस दौर में जब प्रधानमंत्री ने गरीबों को खर्चा कम करने के लिए कहा है, तो क्यों नहीं अपनी सरकार को ऐसा करने का आदेश देते हैं? जितनी फिजूलखर्ची हम करते हैं मंत्रियों के कार्यालयों और कोठियों पर, इसको बंद करना क्या 'देशभक्ति' नहीं होगी मुसीबत के इस दौर में? लुटियंस दिल्ली की जमीन भारत में सबसे महंगी मानी जाती है, तो क्यों नहीं इसका व्यावसायिक इस्तेमाल हो? इस तरह की शुरुआत अगर दिल्ली में होगी, तो राज्यों में भी होने लगेंगी और खूब पैसा बचंगा देश का। फिलहाल प्रधानमंत्री के कहने पर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं उनके मुख्यमंत्री और मंत्री। कभी किसी मुख्यमंत्री की पत्नी साइकिल पर सवार होकर निकलती है टीवी पत्रकारों के सामने, तो कभी कोई मुख्यमंत्री स्कूटर पर सवार होकर निकलते हैं पत्रकारों को दिखाने के लिए। जब आर्थिक संकट पूरे देश में आया है, तो इस तरह के तमाशे बंद होने चाहिए और सरकारी अफसरों और राजनेतों को दिल लगा कर देश का पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। यही होगी असली देशभक्ति। कहा था न मैंने कि जिमखाना क्लब बंद होने से खुल गया है सवालियों का बहुत बड़ा पिटारा।

वे

दिन भी क्या दिन थे जब मैडम दिल्ली को ललकारती रहती थी और हमारे जैसे दर्शक भी कहते थे कि क्या बात है... मैडम योद्धा हैं! मगर बंगाल हार के बाद वे फिर सड़क पर निकलीं, तो वे दृश्य नहीं दिखे, जब हजारों लोग उनके पीछे-पीछे चलते दिखते थे। फिर एक चैनल पर एक 'सेफालाजिस्ट' ने कहा कि 2034 तक भाजपा कहीं नहीं जा रही। तुरंत विपक्ष के एक बड़े नेता का जवाब आया कि हम 'जेन-जी' को समझा देंगे... इसे भगा देंगे...! एक कहिन कि 'जेन-जी' को ने नेपाल और बांग्लादेश में किया, यहाँ भी करेगे, क्योंकि पेपरलरीक है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तानाशाही है। एक सत्ता प्रवक्ता बोला कि 'जेन-जी' तो भाजपा को बंगाल में जिता रही है और मंदिरों में घंटा बजा रही है, हनुमान चालीसा बांच रही है!

इतने पर भी जब कथित 'जेन-जी' विपक्ष के बचाव के लिए नहीं आईं तो विपक्ष 'काकरोच पार्टी' का आह्वान करने लगा! सत्ता प्रवक्ता कहते रहे कि आपके पास 'काकरोच' है, तो हमारे पास 'हिट' है! बहरहाल, एक नामी एंकर अपने चैनल पर 'काकरोच पार्टी' की वेबसाइट से आंकड़े लेकर दिखाता रहा कि किन देशों से इसके कितने फालोअर हैं और कई देशों से तो समान संख्या है। इस 'काकरोच संस्कृति' के आह्वान की राजनीतिक निहितार्थों को खोलते हुए एक एंकर ने कहा कि आप स्वयं तो चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए चाहते हैं कि

मैदान में खिलाड़ी

कोई 'जेन-जी', कोई 'काकरोच' आए जो सत्ता को कुर्सों पर बिठा दे! एंकर ने साफ किया कि 'काकरोच पार्टी' डालर से बनी पार्टी है, यह एक 'इंस्टाग्राम पार्टी' है, यह 'फर्जी' पार्टी है, जिसका डर दिखाया जा रहा है। फिर एक दिन सरकार का झटका 'इंपीरियल जिमखाना क्लब' को जरा जोर से लगा। सरकार ने कह दिया कि जिमखाना क्लब बंद किया जाए! जवाब में इस देश पर एहसान करने वाले एक से एक रणबंकुरे चैनलों के लिए 300 एकड़ जरूरी हैं? सवाल और भी निकल रहे हैं उस पिटारे से। मंत्रियों को अगर इस देश की गरीब जनता के पैसों से बसाना ठीक समझाती है भारत सरकार, तो क्यों नहीं इनको राष्ट्रपति भवन की 300 एकड़ जमीन

बाखबर

सुधीश चवौरी एक दिन सरकार ने कह दिया कि जिमखाना क्लब बंद किया जाए! जवाब में इस देश पर एहसान करने वाले एक से एक रणबंकुरे चैनलों में आकर जिमखाना के 'महान औपनिवेशिक अतीत' और बड़े सेनाधिकारियों के 'अभिजातवाद' की दुहाई देने लगे...! फिर एक ने ताना मारा कि चूँकि प्रधानमंत्री सदस्य नहीं हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो बाकी चर्चक हंसने लगे। वक्ता-प्रवक्ता आजकल यही करते हैं। जब उनकी चलती नहीं, तो जोर-जोर से बोलते रहते हैं, ताकि कोई दूसरे की न सुन पाए। एंकर पता नहीं क्यों, इस तरह के बाधकों को चुप नहीं करते। 'इंपीरियल जिमखाना क्लब' 1913 में अंग्रेजों द्वारा अपने बड़े सेनाधिकारियों के ऐंशो-आराम के लिए बनवाया गया था। यह क्लब नई दिल्ली की सबसे महंगी सत्ताईय एकड़ जमीन पर मामूली किराए पर चलाता है। एक एंकर ने साफ कहा कि जमाना बदल चुका है, अब इस 'औपनिवेशिक अवशेष' को यहां से हटना चाहिए। 'क्लब' वाले कहीं और जमीन खरीद लें और क्लब बना लें। एक एंकर ने तो सीधे यही लाइन दे दी कि 'बुलडोज जिमखाना!' बहरहाल, सबसे बड़ी खबर त्विषा की मौत की रही, जिसका श्रेय

विषमता के प्रतीक

स्थानों का लुप्त होना चेतना के प्रवाह में अवरोध पैदा करने जैसा है। अकेले व्यवसायीकरण को आधुनिकता मान लेना बड़ी भूल साबित होगी। जिमखाना क्लब के बहाने समानता और गैर-कुलीनीकरण की प्रक्रिया पर बहस फलदायी सिद्ध होगी। विषमता से उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को हमने कभी भूदान, तो कभी स्वयंसेवी संस्थाओं के परोपकारी कार्यों के हवाले छोड़ दिया। स्वतंत्र भारत में दो अवसरों पर खास और आम के अंतर पर राज्य ने अपनी स्थिरता की चिंता में कदम उठाया था। पहला जमींदारी उन्मूलन था। यह कठिन और डुक्कर था। पर 1950 के दशक में यह संभव हो पाया। बिहार में इस पर पहला कानून बना था। इसके पक्ष में 1949 में विधानसभा में राज्य के राजस्व मंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय के भाषण में समानता के भाव को नई पीढ़ी में स्थापित करने के लिए

संदर्भ

विषमता और विलासिता, दोनों के पास अपने तर्क होते हैं। उसमें संवेदनशीलता और सरोकार दोनों का कोई स्थान नहीं होता है। यह स्वकेंद्रित होता है, समाज केंद्रित नहीं बन पाता है। जिस देश में जनजातीय समाज, ग्रामीण और शहरी गरीब परिश्रम से अपना अस्तित्व बचाए हुए हों, उसमें सार्वजनिक संपत्तियों का उपयोग खास बने रहने के लिए हो, यह अनैतिक और असंवैधानिक दोनों हैं। एक समृद्ध चेतना के लिए समृद्ध भवन और क्लब शायद आवश्यक नहीं होता है।

विषमता के प्रतीक

पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए था, पर वह अभिलेखागार में कैद है। दूसरा अवसर था प्रीवी पर्स समाप्त करने का। राजा-महाराजाओं को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। राज्यसभा में 1969 में इस पर बहस हुई और उसके बाद लगभग छह सौ राजा-महाराजाओं के विशेषाधिकार समाप्त किए गए। स्वतंत्र भारत में भुखमरी, सम्मानपूर्वक जीवन जीने के साधनों से वंचित लोगों की बड़ी संख्या रही है। इसीलिए स्वतंत्रता के कई दशकों बाद दस करोड़ शौचालय का निर्माण कराना पड़ा और भुखमरी की आशंका तथा संभावनाओं से निपटने के लिए इक्यासी करोड़ लोगों को सरकार निशुल्क खाद्यान्न दे रही है। विषमता और विलासिता, दोनों के पास अपने तर्क होते हैं। उसमें संवेदनशीलता और सरोकार दोनों का कोई स्थान नहीं होता है। यह स्वकेंद्रित होता है, समाज केंद्रित नहीं बन पाता है। जिस देश में जनजातीय समाज, ग्रामीण और शहरी गरीब परिश्रम से अपना अस्तित्व बचाए हुए हों, उसमें सार्वजनिक संपत्तियों का उपयोग खास बने रहने के लिए हो, यह अनैतिक और असंवैधानिक दोनों हैं। इसकी अनुभूति जिमखाना क्लब को जितनी जल्दी होगी, भारत की समृद्धि उतनी ही अधिक होगी। एक समृद्ध चेतना के लिए समृद्ध भवन और क्लब शायद आवश्यक नहीं होता है।

तपती दीवारों के बीच

पल्लवी सक्सेना

सुबह के पांच बजे थे, लेकिन सूरज जैसे सिर पर चढ़कर खड़ा हो। सीमा की आंख खुली तो उसे लगा कि रात जैसे आई ही नहीं। पसीना उसकी गर्दन से होते हुए पीठ तक बह रहा था। उसने पंखे की तरफ देखा, वो अपनी पूरी ताकत से घूम रहा था, पर हवा में टंडक नहीं, सिर्फ गर्मी घुली हुई थी।

वो धीरे से उठी, बाथरूम में गई और नल खोला। पानी भी गुनगुना था। उसने जैसे-तैसे नहा लिया, लेकिन बाहर आते ही फिर वही हालत-पसीना, चिपचिपाहट और घुटन।

‘अब तो नहाना भी मजाक हो गया है’, उसने खुद से कहा और रसोई की तरफ बढ़ गई।

रसोई में कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी भट्टी के सामने आ गई हो। गैस जलाते ही गर्मी दोगुनी हो गई। उसका उस रोज खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। दिल चाहता था कि बस कुछ फल खा ले, टंडा पानी पी ले और दिन काट दे। लेकिन घर था, परिवार था और जिम्मेदारियां थीं, जो चाहने या न चाहने से नहीं रुकतीं। वो चुपचाप सब्जी काटने लगी।

थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। उसका पति अमित बाहर से आया। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे।

‘आज तो बाहर आग बरस रही है,’ उसने आते ही कहा।

सीमा ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली

‘अच्छा यहां टंड लग रही है क्या?’

अमित ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, फ्रिज से बोतल निकालते हुए बोला-

‘कुछ टंडा बना दो पहले, फिर बाद में खाना खा लेंगे।’

सीमा ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया।

दोपहर तक रसोई में खड़े-खड़े गर्मी के मारे उसका सिर भारी हो गया था। फिर भी बिना उफक करे उसने खाना तैयार किया। सब खाने बैठे, पहला कोर मुंह में डालते ही बेटे ने मुंह बनाया-

‘मम्मी, आज सब्जी अच्छी नहीं बनी।’

अमित ने भी बिना देखे कह दिया-

‘थोड़ा नमक कम है शायद?’

सीमा ने एक पल के लिए सबकी तरफ देखा, बिना कुछ बोले उठकर फिर से रोटी सेंकने लगी। उसके अंदर कुछ खोल रहा था। शायद वही गर्मी, जो बाहर थी, अब अंदर भी जगह बना चुकी थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। तभी दरवाजे पर दरतक हुई।

सीमा ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा, बाहर एक दुबला-पतला नन्हा सा बच्चा खड़ा था। चेहरा धूल से भरा हुआ, हॉट सूखे हुए।

कहानी



सीमा एक पल को ठिठकी, बिना कुछ बोले अंदर गई, गिलास में पानी भरा और बाहर आकर बच्चे को दे दिया। बच्चे ने पानी ऐसे पिया जैसे कई दिनों की प्यास बुझा रहा हो।

‘आंटी पानी मिलेगा?’ उसने धीमी आवाज में पूछा।

सीमा कुछ कहती, उससे पहले अंदर से अमित की आवाज आई।

‘अरे, हर रोज आ जाते हैं अपने घर जाकर पियो ना पानी यहां कोई नदी बह रही है क्या? आगे भेजो इसे।’

सीमा एक पल के लिए टिठकी, फिर बिना कुछ बोले अंदर गई, गिलास में पानी भरा और बाहर आकर बच्चे को दे दिया। बच्चे ने पानी ऐसे पिया जैसे कई दिनों की प्यास बुझा रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी राहत थी।

‘धन्यवाद’ कहकर वो चला गया।

सीमा दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। शाम को अमित गाड़ी

लेकर बाहर निकला। थोड़ी देर बाद वापस आया तो चिढ़ा हुआ था।

‘यार, एक तो पहले ही इस देश में किसी को गाड़ी चलाने का सलीका नहीं है, ऊपर से इतनी गर्मी में एक भी पेड़ नहीं बचा इस इलाके में। गाड़ी इतनी गरम हो जाती है कि बैठना मुश्किल हो जाता है।’

सीमा ने धीमे स्वर में कहा-

‘पेड़ लगाने का समय किसके पास है।’

अमित ने उसकी तरफ देखा, मगर कुछ बोला नहीं। रात होने लगी, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। दीवारों जैसे दिन भर की आग उगल रही थी। घर के अंदर हवा ठहरी हुई थी, भारी और तपती हुई। सीमा कुछ सोचकर छत पर चली गई। आसमान में तारे भी जैसे थके हुए लग रहे थे। चारों तरफ सीमेंट ही सीमेंट थी। न हरियाली, न टंडी हवा। वो चुपचाप वहीं पर बैठ गई। उसे अपने बचपन का घर याद आने लगा। आंगन में बड़ा सा नीम का पेड़, दोपहर की टंडी छांव, और मिट्टी की वो सोंधी खुशबू, तब इतनी गर्मी भी नहीं लगती थी।

‘या शायद’ उसने सोचा, ‘तब हम इतने बिगड़े हुए नहीं थे।’

अचानक उसकी नजर नीचे गली में गई। वही बच्चा फिर दिखा। इस बार हाथ में खाली बोतल लिए, पानी की खोज में इधर-उधर देखता हुआ। उसे ऐसी हालत में देख कर सीमा का दिल कसमसा गया। वह तुरंत नीचे उतरी, रसोई में गई और एक मटका पानी से भर दरवाजे के बाहर रख दिया। पास में एक छोटी सी तश्तरी भी पानी भरकर रख दिया पक्षियों के लिए। अमित ये सब देख रहा था।

‘इससे क्या फर्क पड़ेगा?’ उसने पूछा।

सीमा ने उसकी तरफ देखा, इस बार उसकी आंखों में थकान नहीं, एक उद्वेग था।

‘फर्क पड़े या न पड़े शुरुआत तो करनी होगी।’, उसने शांत स्वर में कहा।

अमित चुप हो गया। अगले दिन सुबह वही बच्चा फिर आया। इस बार उसने खुद मटके से पानी लिया। पीकर उसने इधर-उधर देखा, फिर वहीं मटके के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक चिड़िया आई और तश्तरी से पानी पीने लगी। सीमा खिड़की से ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। धीरे-धीरे मोहल्ले के दो-तीन और लोग भी उस मटके का इस्तेमाल करने लगे। खासकर सड़क पर खेलेते बच्चे। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन सबको जरूरत थी। एक दिन पड़ोस की औरत आई और बोली-

‘अच्छा किया तुमने ये खर दिया। बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही थी पानी की। भगवान तुम्हें खुश रखे। भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा और कोई पुण्य नहीं होता बेटी।’ सीमा ने बस मुस्कुरा दिया। उस दिन अमित घर आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा पौधा था। ‘सोचा इसे बाहर लगा देते हैं।’ उसने थोड़ा संकोच से कहा। सीमा ने उसकी तरफ देखा, इस बार उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी।

‘हां! क्यों नहीं, चलो लगाते हैं।’

म्याऊं घर लौट आया

आशा शर्मा

आ

आठ साल का विशाल तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है। विद्यालय से लौटकर खाना खाने बैठा तो उसके हाथ से रोटी का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया। अभी विशाल का खाना समाप्त भी नहीं हुआ था कि जमीन पर गिरे हुए रोटी के टुकड़े को चींटियों ने घेर लिया। विशाल बड़े गौर से चींटियों को देखने लगा। सब चींटियां बड़े ही अनुशासित तरीके से एक लाइन में चल रही थीं।

‘मम्मी! इनको देखो। इसी तरह हम भी अपने स्कूल में चलते हैं। जब हमें प्रार्थना में जाना होता है। क्या चींटियां भी कहीं जा रही हैं?’ उसने उत्सुकता से पूछा।

‘हां! चींटियां बहुत ही अनुशासित होती हैं। इन्होंने अपना भोजन तलाश कर लिया है और अब वे इसे अपने बिल में ले जा रही हैं।’ मम्मी ने उसे समझाया। तभी विशाल को शरारत सूझी और उसने फूंक मारकर चींटियों को इधर-उधर कर दिया। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ ही देर में चींटियां वापस भोजन तक पहुंच गईं और उसे लेकर लाइन बनाकर चलने लगीं। उसे बहुत मजा आया। यह उसके लिए खेल बन गया। वह बार-बार ऐसा करने लगा।

कुछ देर बाद उसने देखा कि वे चींटियां उस रोटी के टुकड़े को घसीट कर बहुत दूर तक ले गई थीं। यह रोटी का टुकड़ा चींटियों के आकार से बहुत बड़ा था और इस समय वे चींटियां उल्टी दिशा में चल रही थीं।

‘मम्मी! जरा देखो तो। यह रोटी का टुकड़ा कितना बड़ा है, और इन चींटियों ने इसे कितनी आसानी से उठा रखा है। लेकिन ये उल्टी क्यों चल रही हैं?’ विशाल ने आश्चर्य से पूछा।

‘हां विशाल! चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। जब इन्हें भोजन में छोटा टुकड़ा मिलता है तो वे उसे आसानी से अपने जबड़े में दबा लेती हैं। लेकिन टुकड़ा बड़ा हो तो बहुत सी चींटियां उसे मिलकर उठाती हैं और उसे घसीटने के लिए इन्हें विपरीत दिशा में चलना पड़ता है।’ मम्मी ने फिर समझाया।

‘लेकिन उल्टा चलने पर इन्हें दिखाई कैसे देता है? क्या वे अपने घर का रास्ता नहीं भूलती?’ विशाल आज चींटियों के बारे में जानकारी पाकर बहुत हैरान हो रहा था। उसके लिए यह किसी रोचक कहानी जैसी थी।

‘चींटियों के शरीर से एक विशेष प्रकार का रसायन निकलता है जिसे फेरोमोन कहते हैं। जब चींटियां भोजन की तलाश में निकलती हैं तो रास्ते में इसे छोड़ती हुई जाती हैं और वापसी में उसी की गंध के सहारे अपने घर तक आती हैं।’ मम्मी ने बताया तो विशाल की आंखें हैरानी से फैल गईं।

‘कितना ही अच्छा होता यदि ऐसा ही कोई रसायन हमारे म्याऊं के शरीर से भी निकलता। फिर वह भी नहीं खोता। वापस घर लौट आता। है न मम्मी!’ विशाल अपने खोये हुए बिल्ली के बच्चे को याद करते हुए उदास हो गया।

‘ऐसा नहीं है बेटा! तुम्हारा म्याऊं और अन्य जानवर भी घर से दूर जाते समय अपने शरीर से एक तीव्र गंध छोड़ते हैं जो उन्हें वापस लौटने में मदद करती है। इसी प्रकार पक्षी भी तो अपने दिशा ज्ञान के आधार पर ही वापस अपने घोंसले में लौटते हैं। याद है न! किस तरह पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भी अपना मूल स्थान नहीं भूलते। हो सकता है कि तुम्हारे म्याऊं को उसके साथी मिल गए हों और वह उनके साथ चला गया हो। आखिर सभी अपने साथियों के साथ ही रहना पसंद करते हैं न? इसलिए उदास नहीं होते। जरा सोचो! प्रकृति ने सभी प्राणियों को कितनी अलग-अलग विशेषताएं दी हैं। तुम्हारे म्याऊं को भी तो पेड़ पर चढ़ने की विशेषता दी है न। याद है, कितनी फुर्ती से वो नीम के पेड़ पर चढ़ जाता था।’ मम्मी ने विशाल को म्याऊं की अच्छी बातें याद दिलाते हुए कहा। हालांकि उन्हें भी बिल्ले की उतनी ही याद आती थी जितनी विशाल को।

बाल कथा



तुम्हारा म्याऊं और अन्य जानवर भी घर से दूर जाते समय अपने शरीर से एक तीव्र गंध छोड़ते हैं जो उन्हें वापस लौटने में मदद करती है। इसी प्रकार पक्षी भी तो अपने दिशा ज्ञान के आधार पर ही वापस अपने घोंसले में लौटते हैं। याद है न! किस तरह पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद भी अपना मूल स्थान नहीं भूलते।

‘हां मम्मी! मुझे याद आ रहा है कितना फुर्तीला था वो विशाल मुस्कुरा दिया।

‘हां! तो अब मुस्कुराओ और मेरी पहेली को पूरा करो। चींटी मेहनती...म्याऊं फुर्तीला...और टामी?’ मम्मी ने बात बीच में छोड़ दी।

‘टामी चौकन्ना...!’ विशाल ने बात पूरी की और ताली बजाकर हंसने लगा। अचानक उसका ध्यान बाहर पोर्च की तरफ गया। उसे वह दिखा जिसकी उम्मीद छोड़ चुका था।

‘मम्मी! देखो, अपना म्याऊं।’ कहते हुए विशाल दरवाजा खोलकर बाहर की ओर लपका। उसके दरवाजा खोलने की ही देर थी कि म्याऊं फुर्ती से घर के भीतर घुस आया। अब वह अपना पेट उधाड़कर फर्श पर लोट रहा था।

‘यह वापस कैसे आया?’ विशाल ने म्याऊं का पेट सहलते हुए मम्मी से पूछा।

‘मैंने कहीं पढ़ा था कि बिल्लियां यदि रास्ता भटक जाएं तो उनके ‘लिटर’ यानी शौच की गंध रास्ता पहचानने में उनकी सहायता करती है। यही सोचकर मैंने म्याऊं का ‘लिटर बाक्स’ बाहर खुले में रख दिया। यह सोचकर कि यदि वह वापस आना चाहे तो उसे रास्ता मिल सकता है। देखो, मेरी युक्ति काम कर गई। हमारा म्याऊं अब हमारे साथ है।’ मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा तो विशाल मम्मी से लिपट गया। म्याऊं भी उनके पांवों से लिपटकर अपनी खुशी जाहिर कर रहा था। अब म्याऊं को भूख भी तो लगी थी।

जनसत्ता सरोकार

ह

हमारा दिमाग जिसका अंदाजा नहीं लगा सकता, उसे ही अपराध कहते हैं। जहां पर हमारी सुरक्षात्मक सोच खत्म हो जाती है, दरअसल अपराध वहीं से शुरू होता है।

त्विषा शर्मा की मां को भी आम लोगों की तरह अंदाजा नहीं था कि अपराध की गति कितनी तेज होती है। त्विषा शर्मा की मौत के बाद उनकी मां रेखा शर्मा ने अपनी बेटी के वाट्सएप संदेशों को दिखाया। यह सबूत था कि त्विषा शर्मा पर ससुराल में अत्याचार हो रहे थे।

अपराध की तरह सोशल मीडिया का व्यवहार भी अविश्वसनीय होता है। सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका त्विषा शर्मा की मां को कोसने लगा। बेटी के इस संदेश को देखते ही उसे क्यों नहीं ले आई? त्विषा की मौत के लिए उनकी मां को भी जिम्मेदार ठहराया गया। सोशल मीडिया की अदालत के परे आज त्विषा शर्मा का परिवार एक मिसाल बन चुका है। आपराधिक मानसिकता और अपराधियों पर हम काबू नहीं पा सकते हैं। लेकिन हम अपराध के खिलाफ डट कर खड़े होना सीख जाएं तो आने वाला समय जरूर बदल सकता है। अपराधी को सजा मिलने को इंसफ कहा जाता है।

जनसत्ता सरोकार

बि

लियां क्या इंसानों से बात कर सकती हैं? क्या आसमान से मछलियां बरस सकती हैं? क्या जंगल के किसी छोर से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल सकता है? इन सवालों के जवाब जैसा जादुई यथार्थ है काफका तिमुरा की दुनिया में। ‘काफका आन द शोर’-हारूकी मुराकामी की एक ऐसी रचना है जो जीवन के विरोधाभासों को एक कुंजी की तरह समेटती है। काफका तिमुरा एक पंद्रह साल का किशोर है। मुराकामी अपनी खास शैली में इस किशोर किरदार के जरिए निर्याति और पहचान जैसे कठोर सवालों से सामना करावते हैं।

काफका एक ऐसा किशोर पात्र है, जिसे समझने की प्रक्रिया में पाठक खुद को परिपक्व महसूस करते हैं। इस उपन्यास को लेकर हर पाठक का अपना खास पाठ होता है। साहित्यिक बाल किरदारों की तरह काफका भी अपनी उम्र के अनुपात में बहुत गंभीर लगता है। उसका अकेलापन उसे आत्मविश्लेषण के अध्यायों से गुजारता है। उपन्यास की शुरुआत में ‘क्रो’ काफका से कहता है-कभी-कभी किस्मत किसी रेत की आंधी की तरह होती है।

काफका की मां उसे चार साल की उम्र में अकेला छोड़ कर चली गई है। मां के प्यार से वंचित काफका का कोई भावनात्मक सहारा नहीं है। अपना साथ देने के लिए वह एक काल्पनिक दोस्त तैयार करता है

संघर्ष का सामूहिक संबल



मार्गदर्शन

यह इंसफ भी आगे के समय के लिए सामूहिक संबल पैदा करता है। आम लोगों को गलत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत मिलती है।

त्विषा शर्मा की मौत के बाद इस मामले को शुरू से देख रही टीवी पत्रकार ने पिछले दिनों इस साहसी परिवार के सच को सामने रखा। जिस गिरिबाला सिंह ने अग्रिम जमानत का जुगाड़ कर लिया था, उनकी गिरफ्तारी यूं ही नहीं हुई। बकौल पत्रकार, एक पूरा परिवार एक अनजान शहर में व्यवस्था से भिड़ गया। परिवार ने इस बात की

परवाह नहीं की कि लोग उनकी बेटी के निजी जीवन के बारे में क्या कह रहे हैं। उन्होंने व्यवस्था की हर खामी पर अंगुली रखी और मीडिया के जरिए इन खामियों को आम से लेकर खास तक की आंखों में पहुंचाया।

त्विषा शर्मा क्या थी, कैसी थी इसका आकलन न तो आम लोग कर सकते हैं और न करना चाहिए। त्विषा शर्मा के परिवार के जज्बे और उनकी इंसफ मांगती रही भाषा इस बात का सबूत है कि उनके घर का व्याकरण प्यार, सद्भाव और बराबरी वाला होगा। शादी हमेशा से एक अनिश्चित चीज रही है। चाहे वह प्रेम विवाह हो, परिवार के द्वारा तय किया गया हो, परेशानियां किसी में भी हो सकती हैं। किसी भी तरह से बने संबंध में एक बिंदु पर महसूस हो सकता है कि आप आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति के साथ फंस गए हैं। इस पहचान के होते ही अपराध की गति और तेज हो जाती है। पर हम अपराधियों के चंगुल में फंसे व्यक्ति को ही दोषी बताने लगते हैं।

पुलिस, कानून, अदालत इसलिए हैं कि अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराध के शिकार लोगों को व्यवस्था से भी लड़ना पड़ता है। उन्हें खुद साबित करना पड़ता है कि वे अपराध के शिकार हुए हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण लड़ाई में हौसला न हार कर त्विषा शर्मा के परिवार ने बड़ी उम्मीद जगाई है।

काफका और उसके मन का कौआ

जनसत्ता सरोकार

अमर किरदार



मुराकामी ने काफका को बाल नायक की तरह नहीं गढ़ा है। वह न तो पारंपरिक कहानियों का चंचल बालक है, न हैरी पाटर की तरह साहसी और न उसके पास अलादीन की तरह जादुई कारनामे करने वाला कोई चिराग है।

जिसे ‘द बाय नेम्ड क्रो’ कहा जाता है। सबसे अहम बात यह है कि मुराकामी ने काफका को पारंपरिक

बाल नायक की तरह नहीं गढ़ा है। वह न तो आम कहानियों का चंचल बालक है न हैरी पाटर की तरह साहसी, और न उसके पास अलादीन की तरह जादुई कारनामे करने वाला कोई चिराग है।

इस दुनिया की व्यवस्थागत संरचना की सबसे छोटी इकाई परिवार है। काफका के जरिए पाठक परिवार की अनुपरिस्थिति में एक किशोर की मनोवैज्ञानिक यात्रा से रूबरू होते हैं। मां की अनुपरिस्थिति में बच्चा अपने मन से बात करता है। जीवन के अनुसुलझे सवाल उसके मन में एक भूलभूलैया बनाते हैं, जिसमें वह भटकता रहता है। परिवार की एक भूमिका स्मृति का निर्माण करना भी है। एक सामान्य बचपन और मां के बिना किसी बच्चे की स्मृति और पहचान का संघर्ष मुराकामी काफका के जरिए दिखाते हैं।

काफका के अंदर कौए के रूप में एक काल्पनिक साथी है। कौए को मुराकामी ने प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। सबसे पहले तो यह काफका के जीवित रहने की इच्छा का प्रतीक है। वह अपने अवचेतन मन को ही अपना मार्गदर्शक बना लेता है। जब काफका किसी बात से डरता है तो अवचेतन का कौआ उसे निर्भीक बनने की प्रेरणा देता है। वहीं उपन्यास में जंगल को भी खुद को खोजने की यात्रा और जीवन-मृत्यु के संघर्ष के तौर पर देखा जाता है। इन सबके बीच सवाल उठता है कि शक्ति की परिभाषा क्या है? एक क्लिष्ट बाल किरदार के जरिए मुराकामी संदेश देते हैं कि असली शक्ति अपने डर का सामना करने में है।

मुट्ठी भर खुबानी सेहत की कहानी

सू

खे मेवे तो हम सभी खाते हैं, लेकिन सुनहरे-भूरे रंग की खुबानी की ओर हमारा ध्यान कम ही जाता है। यह ऐसा प्राकृतिक फल है जो कच्चा भी खाया जाता है और सुखा कर कर भी। मगर जब उसे सुखा दिया जाता है, तो यह पोषक तत्वों से भरपूर मेवा बन जाता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक के लोगों के लिए यह फायदेमंद है। अगर शरीर में ऊर्जा कम हो रही हो, तो बस मुट्ठी भर सूखी खुबानी खाएँ और सेहतमंद रहिए।

पोषण से भरपूर

इसमें पर्याप्त मात्रा में कैलोरी होती है। निश्चित मात्रा में फाइबर के साथ आयरन भी पाया जाता है। सबसे खास बात यह कि हड्डियों को मजबूत बनाने वाले तत्व जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम भी इसमें पाए जाते हैं। शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बीटा कैरोटीन भी इसमें मौजूद होता है जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। वहीं विटामिन 'ए' और 'सी' की मात्रा भी खुबानी की पोषकता को समृद्ध करती है। इसमें पोटेशियम की मात्रा भी पाई जाती है।

लौह-तत्वों की कमी करे दूर

शरीर में लौह तत्वों की कमी से आम तौर पर लोग कभी न कभी ज़रूर प्रभावित होते हैं। महिलाओं में प्रायः लौह तत्व की कमी हो जाती है। इससे उन्हें कमजोरी और थकान महसूस होती है। पर्याप्त नींद लेने पर भी लगातार थकान महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि शरीर में लौह तत्व की कमी हो गई है। ऐसे में आसान-सा नुस्खा है। अगर रात भर भिगो कर रखी खुबानी खाएँ, तो लौह तत्वों की कमी पूरी हो जाती है। तीन-चार सूखी खुबानी के सेवन से हीमोग्लोबिन के स्तर में भी सुधार होता है। इसके नियमित सेवन से शरीर को स्फूर्ति मिलती है। गर्भावस्था के दौरान यह महिलाओं के लिए भी फायदेमंद है।

खिली रहे त्वचा

सूखी खुबानी को त्वचा स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है। सबसे बड़ी बात कि यह बड़ती उम्र के असर को भी रोकता है। दरअसल, इसमें मौजूद विटामिन 'ए' और 'सी' मिल कर त्वचा की लोच बढ़ाते हैं, जिससे झुर्रियाँ कम होती हैं। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन आंतरिक रूप से त्वचा

थूप से सुरक्षा करता है। इससे 'सनबर्न' का खतरा कम हो जाता है। कुल मिला कर खुबानी का नियमित सेवन किया जाए, तो इससे त्वचा की चमक तो बढ़ती ही है, चेहरे पर बन रही महीन रेखाएँ भी कम होने लगती हैं। खुबानी को पीस कर इसमें शहद और नींबू मिला कर लेप बनाएँ और इसे चेहरे पर लगाएँ। इससे चेहरा खिल उठता है।

हड्डियाँ करे मजबूत

सूखी खुबानी में ऐसे कई महत्वपूर्ण खनिज होते हैं जो हड्डियों को मजबूत करते हैं। इससे आस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो जाता है। दरअसल, इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों की संरचना को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा आंखों के लिए भी खुबानी बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद विटामिन 'ए' और बीटा कैरोटीन कमजोर दृष्टि को ठीक



सूखी खुबानी को त्वचा स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है।

इ

तिहास का हाथ पकड़कर भविष्य का सफर तय किया है किताबों ने। साधारण-सी दिखने वाली पुरानी जिल्द और पीले पड़ गए पन्नों वाली किताब जिसमें समय की सीलन महक रही होती है, जब घर के किसी कोने से अनायास ही हमारे हाथों में पड़ जाती है, तो हम कितने ही बरस पीछे का सफर फलक झपकते तय कर लेते हैं। उन पन्नों के बीच वे सुखे फूल आज भी यादों की खुशबू से महक उठते हैं। पत्थरों पर चिह्न बनकर उभरने और उकरने से लेकर, पत्तों, हस्तलिखित पांडुलिपियों में ढलते हुए कागज पर स्याही से पहचान पाने और किताबों की मजिल पाने तक शब्दों ने सदियों का दिलचस्प सफर तय किया है। आज भी समाज, सभ्यता और संस्कृति को जानने-समझने के लिए किताबों ही सबसे प्राथमिक दस्तावेज मानी जाती हैं। किरसे-कहानियाँ, ज्ञान-विज्ञान, कला, संगीत, नृत्य, साहित्य, धर्म, राजनीति और न जाने कितनी ही सदियों के इतिहास की साक्षी रही हैं किताबें।

कहावत है कि किसी की भी गलती या बुराई हमेशा रेत पर लिखना और अच्छाई को पत्थर पर उकेरना, क्योंकि पहाड़ के पत्थर समय के भाल पर सदियों खड़े रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों को संदेश हमारे पूर्वजों ने पहाड़ों पर अपने चिह्न और लिखावट से ही छोड़े हैं। वहीं रेत स्मरण शक्ति में भूलने की गुंजाइश और ज़रूरत का प्रतीक बनी, ताकि कुछ भी अनुपयोगी जीवन की सरलता और तरलता को धीमा न कर दे। यानी शब्द और लिखावट के निशान जगजाहिर हैं। जब शब्दों की किताबों की गोद मिली, तो किताबों ने भी पुस्तकालयों के घर बसाए।

पुस्तकालय का प्रकाश

भारत का सबसे बड़ा और पुराना पुस्तकालय 'नेशनल लाइब्रेरी आफ इंडिया' कोलकाता में है, जिसकी स्थापना 1836 में कलकत्ता लाइब्रेरी के रूप में की गई थी। तमिलनाडु के तंजावुर में सरस्वती महल लाइब्रेरी देश का सबसे पुराना किताबघर है, जहाँ ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियाँ संरक्षित हैं। सदियों से किताबों का स्थायी ठौर रहे हैं किताबघर। किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण इन्हीं पुस्तकालयों के हवाले रहा है। शायद इसीलिए कहा गया है कि किसी सभ्यता और देश को मिटाना हो, तो वहाँ के पुस्तकालयों को तबाह कर दो। इतिहास गवाह है कि

दुनियाभर के कई पुस्तकालय इसी सनक का शिकार हुए। एलेक्जेंड्रिया, जिसे तीन शताब्दी पूर्व प्लेटोनी शासकों ने मिस्र की सांस्कृतिक धरोहर संजोने के लिए बनाया था, कई बार सुलगा। इसमें हजारों की संख्या में पांडुलिपियाँ और लेख मौजूद थे। दुनियाभर के नामी लेखकों और उनके विभिन्न विषयों के लेखों की प्रति भी यहाँ रखी जाती थी।

ज्ञान के केंद्र

नालंदा मठ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, वास्तुकला ने अभूतपूर्व विकास किया। नालंदा मठ पांचवीं से बारहवीं शताब्दी तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा, जहाँ चीन, जापान, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया समेत दुनियाभर से विद्यार्थी जुटते थे, जिनमें तकरीबन दस हजार विद्यार्थी और दो हजार शिक्षक थे। नालंदा उस समय बौद्ध धर्म का केंद्र

हुआ करता था, लेकिन मठ का धर्म और शिक्षा से बराबर सरोकार था। रत्नसगर, रत्नरंजका और रत्नदड़ी वहाँ के पुस्तकालय के विभाग थे, जहाँ धर्म, इतिहास, कानून, विज्ञान, खगोल, भूगोल, व्याकरण, साहित्य समेत हर विषय की पांडुलिपियाँ और किताबें थीं। इनकी सही संख्या किसी को नहीं मालूम। इतिहासकार भी केवल अंदाजा ही लगाते रहे हैं कि इनकी संख्या हजारों में रही होगी। अब डिजिटल स्वरूप की किताबों को खोजना जितना आसान है, उससे भी ज्यादा सहज है दुनियाभर की किताबों तक पहुँचना। सिर्फ एक क्लिक और सब स्क्रीन पर। सरकारें लगातार अपने-अपने स्तर पर पुस्तकालयों का डिजिटल आधुनिकीकरण कर रही हैं। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के अलावा सार्वजनिक पुस्तकालय भी डिजिटल रूप में विकसित किए जा रहे हैं। शुरुआती दौर में पुस्तकालय जहाँ केवल साहित्यिक और सांस्कृतिक दस्तावेज संरक्षण का काम करते थे, वहीं अब पुस्तकालय ई-पुस्तकें, ई-पत्रिकाएँ, लेख, ऑडियो-वीडियो सामग्री, शोध और शैक्षणिक डेटा, ऑडियो किताबें भी उपलब्ध करा रहे हैं। डिजिटल



दुनियाभर के कई पुस्तकालय इसी सनक का शिकार हुए।

कहावत है कि किसी की भी गलती या बुराई हमेशा रेत पर लिखना और अच्छाई को पत्थर पर उकेरना, क्योंकि पहाड़ के पत्थर समय के भाल पर सदियों खड़े रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों को संदेश हमारे पूर्वजों ने पहाड़ों पर अपने चिह्न और लिखावट से ही छोड़े हैं। वहीं रेत स्मरण शक्ति में भूलने की गुंजाइश और ज़रूरत का प्रतीक बनी।

पुस्तकालय के इस अवतार ने पाठकों और सामग्री के बीच उपलब्धता की खाई को पाटने का भी काम किया है।

बदलते रिश्ते

समय बदलने के साथ ही किताबों के साथ पाठकों का रिश्ता भी बदला है। डिजिटल युग ने किताबों तक पहुँच आसान भले ही कर दी है, लेकिन किताबों से पाठकों के जुड़ाव पर असर पड़ा है। कोरोना काल ने डिजिटल पढ़ाई, ई-बुक संस्कृति को नई पहचान ज़रूर दी, लेकिन यह भी सच है कि कोरोना काल का आड़ में कितनी ही जानी-मानी पत्रिकाएँ अपना भौतिक स्वरूप हमेशा के लिए खो बैठीं और कई पत्रिकाओं का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। कुछ पत्रिकाओं को ई-रूप देकर न केवल प्रिंटिंग लागत, यातायात लागत से छुटकारा मिला, बल्कि 'ई-सब्सक्रिप्शन' ने अग्रिम भुगतान से कमाई के रास्ते भी खोले।

जब-जब पढ़ने की बात होती है तो किताबों का भौतिक रूप ही जेहन में आता है। ऐसे लोगों की आज भी कमी नहीं है, जिन्हें किताबों का आनलाइन रूप जरा भी नहीं पचता। इसमें दो राय नहीं कि किताबों की छूकर पढ़ने का एहसास हमेशा ही डिजिटल रूप से नदारद रहेगा। अक्सर किताबों का जिक्र करते हुए हम भूल जाते हैं बच्चों की और शायद अपने बचपन की भी। पंचतंत्र, चंपक, चाचा चौधरी, अमर चित्र-कथा, अकबर-बीरबल, तेनाली राम की ढेरों कहानियाँ और हास्य के चटकतिले रंगों के किस्वर किसी की स्मृति से ओझल नहीं हुए हैं और न ही पुराने। न ये कहानियाँ पुरानी हुईं और न ही इनके किस्वर। इनकी कहानियों का रोमांच उनके चित्रों में ज्यादा था। बाल साहित्य आज भी छप और बिक रहा है, लेकिन अब किरसे-कहानियों की वह दुनिया जादू की तरह नहीं खुलती और बच्चों में भी किताबों को लेकर रोमांच गायब है।

घरेलू कार्यों में छिपा तंदुरुस्ती का राज

भा

रतीय समाज में पिछले कुछ वर्षों से जिम में जाकर कसरत करने का चलन बढ़ रहा है। बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि छोटे-छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी अब जगह-जगह जिम खुल गए हैं। व्यायाम करना सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन क्या इसका प्रभावी विकल्प सिर्फ जिम और योग केंद्र ही हैं। विचारणीय तथ्य यह है कि लोग अपने घर के काम से परहेज करते हैं, उसके लिए घरेलू सहायक रखते हैं और खुद पैसे देकर जिम में पसीना बहाते हैं। यानी घरेलू कार्य जो हमारी पारंपरिक जीवनशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, समाज के एक वर्ग ने उसे खुद से अलग कर दिया है और उनकी जगह 'जिम संस्कृति' को अपना लिया है। घर पर रोजमर्रा के ऐसे कई कार्य हैं, जिन्हें करने से शरीर का अच्छा-खास व्यायाम हो जाता है, जिससे व्यक्ति खुद को सेहतमंद बनाए रख सकता है।

शान का सवाल

इसमें चोराय नहीं कि आज के तकनीकी दौर में मनुष्य मानसिक तौर पर भले ही सक्रिय रहता है, लेकिन शारीरिक रूप से वह आलसी होता जा रहा है। जो लक्ष्य घर पर रोजमर्रा के कार्यों के साथ आसानी से हासिल किया जा सकता है, उसे पैसे देकर मशीनों के जरिए पूरा करने की कोशिश की जाती है। दिनभर के छोटे-छोटे कार्यों, जैसे

झाड़ू-पोंछा करने, बर्तन धोने, बाजार से सामान लाने और साज-सज्जा को व्यवस्थित करने से पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। सुबह या शाम की सैर और तेज चलकदमी सेहतमंद रहने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। मगर समाज का एक बड़ा हिस्सा अब इन कार्यों को अपने सम्मान और शान के खिलाफ मानता है।

दिनचर्या में बदलाव

यह विचित्र विरोधाभास है कि लोग आज थोड़ा सा पैदल चलने से भी परहेज करते हैं और घर की

साफ-सफाई में भी शर्म महसूस करते हैं। मगर वहीं लोग जिम में जाकर 'ट्रेडमिल' पर दौड़ लगाते हैं, मशीनों के सहारे उठक-बैठक करते हैं और यहाँ तक कि पोंछा लगाने की प्रक्रिया से जुड़ी गतिविधियों में भी हिस्सा लेते हैं। यह प्रश्न समाज में भीड़ के साथ चलने के मनोविज्ञान से भी जुड़ा है, जिससे हमारी जीवनशैली में बदलाव आ रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि अगर हम अपनी पारंपरिक दिनचर्या के अनुसार काम करें, तो न केवल स्वस्थ रहेंगे,

शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त नजर न आएँ, तो उनके भीतर कुंठा का भाव पैदा होने लगता है। जबकि घरेलू कार्यों में न तो समयसमया होती है और न पैसा तथा समय बर्बाद होने की चिंता। ऐसे में जरूरी है कि इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए कि सेहतमंद रहने के लिए कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर है।

घरेलू कार्य, जो हमारी पारंपरिक जीवनशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, समाज के एक वर्ग ने उसे खुद से अलग कर दिया है और उसकी जगह 'जिम संस्कृति' को अपना लिया है।

बल्कि पैसे और समय की बर्बादी से भी बच सकते हैं।

मानसिक दबाव

जिम में जाकर व्यायाम करने की प्रक्रिया में लोग मानसिक तनाव का शिकार भी हो रहे हैं। उन पर इस बात का दबाव होता है कि उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर ही व्यायाम के विभिन्न चरणों को पूरा करना होता है, वहीं अगर लंबे समय तक मशीनों पर कसरत करने के बाद भी वे शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त नजर न आएँ, तो उनके भीतर कुंठा का भाव पैदा होने लगता है। जबकि घरेलू कार्यों में न तो समयसमया होती है और न पैसा तथा समय बर्बाद होने की चिंता। ऐसे में जरूरी है कि इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाए कि सेहतमंद रहने के लिए कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर है।

खानपान में कोताही

कमजोर हड्डियाँ

खा

नपान में लापरवाही से लोगों की हड्डियाँ अब कमजोर हो रही हैं। एक समय था जब संयमित खान-पान से लोगों की हड्डियाँ मजबूत रहती थीं। उम्र ढलने पर भी कोई समस्या नहीं होती थी। मगर आज युवाओं की भी हड्डियाँ कमजोर होने लगी हैं। आलस्य ने यह समस्या और बढ़ा दी है। इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हड्डियाँ ही हैं जो पूरे शरीर को संभाले रहती हैं। अब अंधेड़ावस्था घर होते ही हड्डियाँ कमजोर पड़ने लगी हैं। लिहाजा लोगों को सचेत होना चाहिए। आस्टियोपोरोसिस जैसी दिक्कत जब शुरू होती है, तब लोगों को चलने-फिरने में परेशानी महसूस होने लगती है।

समस्या की जड़

हड्डियों के कमजोर होने की समस्या कोई एक दिन में नहीं होती। यह धीरे-धीरे सामने आती है। जब चलने में दिक्कत होने लगती है, तभी लोग चिकित्सक के पास जाते हैं। अगर पहले से सजग रहें, तो शायद नौबत ही न आए। दरअसल, हमारे शरीर में हड्डियाँ प्रोटीन के रेशे पर कैल्शियम जमा होने से बनती हैं। इस कैल्शियम को जमाने का काम विटामिन-डी करता है। गौर करने की बात है कि जब शरीर में इस विटामिन की कमी होती है, तो प्रोटीन के रेशे कमजोर होने लगते हैं। इससे आस्टियोपोरोसिस की समस्या होने लगती है। ऐसी हालत में हड्डियाँ इतनी कमजोर हो जाती हैं कि मामूली झटका लगने पर भी इसके टूटने का खतरा रहता है।

उम्र का असर

आम तौर पर यह समस्या उम्र बढ़ने पर शुरू होती है। हालाँकि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में यह समस्या अधिक होती है। रजोनिवृत्ति शुरू होने से पहले उनमें यह दिक्कत होती है। यही वह समय है जब महिलाओं में मासिक चक्र बंद होने लगता है। ज्यादातर महिलाओं में यह अवस्था 45 से 50 वर्ष की

उम्र में शुरू होती है। शोषकताओं के मुताबिक हड्डी में पतलेपन और घनत्व की कमी के कारण इसके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। यह स्थिति अस्थि मज्जा में रसा कोशिकाओं की वृद्धि के साथ पैदा होने लगती है। एक अध्ययन के मुताबिक सीपीएच-बीटा नाम का प्रोटीन हड्डियों के बनने में मददगार कोशिकाओं को शरीर में बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। समय पर पता न चलने से इसका उपचार नहीं होता। इससे बुजुर्गों में यह समस्या बढ़ रही है। हड्डियों में कमजोरी के कारण उन्हें कमर और पीठ दर्द की शिकायत रहती है। नाखून कमजोर पड़ने लगते हैं। रीढ़ की हड्डियाँ सिकुड़ने से कद थोड़ा कम होने लगता है।

निष्क्रियता के जोरिम

हड्डियों में दिक्कत बढ़ने पर लोग घरेलू काम करने और आसपास पैदल जाने से भी कतराने लगते हैं। रोजमर्रा के जीवन में उनकी निष्क्रियता बढ़ने लगती है। जोड़ों में अकड़न बढ़ जाती है। ऐसे में लोगों को हल्का व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। जोड़ों में लचीलापन लाने के लिए योगासन और पैदल चलना अच्छा माना गया है। हल्का वजन उठाने से मांसपेशियों को भी मजबूती मिलती है। हालाँकि अधिक वजन उठाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कूल्हे और घुटने पर दबाव बढ़ता है। हड्डियों के घिसने का भी डर रहता है।

पोस्टिक आहार ज़रूरी

उम्र बढ़ने पर कैल्शियम से भरपूर भोजन लेना ज़रूरी है। इनमें पत्तेदार सब्जियाँ के साथ पनीर, दूध और दही शामिल करें। इसके लिए सोया, दाल, झींगा और अंडे लिए जा सकते हैं। विटामिन-डी की कमी पूरी करने के लिए सुबह की धूप अच्छी मानी गई है। सुखे मेवे में अखरोट लेना भी फायदेमंद है। हड्डियाँ कमजोर हो रही हों, तो शराब और धूम्रपान से बचना चाहिए। वैसे भी स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक हैं। (यह लेख सिर्फ सामान्य जानकारी और जागरूकता के लिए है। उपचार या स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए विशेषज्ञ की मदद लें।)

पौष्टिकता का साथ, स्वाद लाजवाब

मटर पुलाव

मटर को कई सब्जियों के साथ मिलाकर बनाया जा सकता है। इसमें हल्की मिठास होती है और इससे बनने वाला व्यंजन भी लाजवाब होता है। अगर कभी भोजन बनाने के लिए समय कम हो, तो मटर पुलाव शटपट बनाया जा सकता है। यह पौष्टिक होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी होता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को यह पसंद आता है।

सामग्री

बासमती चावल: 200-250 ग्राम, हरी मटर: 150 ग्राम, प्याज: एक, टमाटर: दो, अदरक-लहसुन का पेस्ट: दो चम्मच, हरी मिर्च: दो-तीन, हरा धनिया: आधी कटोरी, पुदीने के पत्ते: पांच-सात, गरम मसाला पाउडर: एक चम्मच, कटा हुआ नारियल: तीन-चार चम्मच, नमक: स्वादानुसार।

विधि

बासमती चावल को धोकर करीब आधे घंटे तक पानी में भिगो लें। इसी बीच, एक कड़ाही में तेल गरम



पपीते का परांठा

प

पीता कच्चा हो या पका हुआ, यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कच्चे पपीते की सब्जी घरों में अक्सर बनाई जाती है। मगर कच्चे पपीते के परांठे बनाए जाएँ, तो इसका जायका बेहतरीन हो जाता है।

सामग्री

गेहूँ का आटा: 200 ग्राम, कच्चा पपीता: दो (मध्यम आकार के), हरा धनिया (बारीक कटा हुआ), अदरक: एक इंच, हरी मिर्च: तीन-चार, लहसुन: छह-सात कलियाँ, अमचूर: एक चम्मच, अजवाइन: एक चम्मच, कसूरी मेथी: एक चम्मच, नमक: स्वादानुसार।

विधि

सबसे पहले एक थाली में गेहूँ का आटा लें और उसमें हल्का सा नमक, अजवाइन तथा तेल डाल कर अच्छी तरह मिला लें। फिर इसे गुनगुने पानी के साथ गूंधें और कुछ देर तक ढक कर दें। इसे दही या रायता के साथ गरमागरम परोसें।



Last Day To Join Private Channel. Closing entry for new members Now.



[Click here
to join](#)

◆ Indian Newspaper

1) Times of India

2) The Hindu

3) Business line

4) The Indian Express

5) Economic Times

And more Newspapers

◆ International Newspapers channel

[European, American, Gulf & Asia]

◆ Magazine Channel

National & International

[General & Exam related]

◆ English Editorials

[National + International Editorials]

◆ Lifetime validity at just 19 Rupees 📌

Trust me... this will be your best purchase of 2026